THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI KAPIL SIBAL): Sir, I lay a statement on the status of implementation of recommendations contained in the Hundred Fifty-fifth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests.

The present status of implementation is as per the annexure which is laid on the Table of the House.

---

**GOVERNMENT BILLS**—Contd.

**The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Bill, 2006**

**MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Scheduled Tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Bill 2006.**

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI P.R. KYNDIAH): Sir, I beg to move:

That the Bill to recognise and vest the forest rights and occupation in forest land in forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for generations but whose right could not be recorded; to provide for a framework for recording the forest rights to vested and the nature of evidence required for such recognition and vesting in respect of forest land, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

*The question was proposed.*

**श्री कांजीभाई पटेल** (गुजरात): माननीय उपसभापति महोदय, आज इस गौरवान्वित सदन में the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Bill, 2006 पर बोलने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस बिल के लिए एक जेपीसी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया है, "All forest-dwelling Schduled Tribes and other traditional forest dwellers must be rehabilitated strictly in compliance with ILO-107 Convention, and in strict compliance with the policy of prior consent."

बिल लाने का महत्वपूर्ण करण यह है कि कई देश आईएलओ में इकट्ठे हुए थे और उनकी जो

सिफारिश थी, उसके मुताबिक यह बिल इस सदन में लाया गया है। मान्यवर उपसभापति महोदय, मैं और मेरा दल अनुसूचित जनजाति के वनभूमि पर अधिकार की बात हो या उनके अन्य अधिकारों की बात हो, हमेशा इसका पक्षधर रहा है और जब-जब मौका मिला, तब तक जनजातियों को उनके अधिकार हमने दिलाएं हैं। इतना ही नहीं, कई मामलों में अन्य दलों से हम अग्रसर हैं, यह मैं तथ्यों के आधार पर दावे के साथ कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी, तब मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों को करीब 82 हजार हेक्टेयर वनभूमि के अधिकार दिए गए थे। मैं जब गुजरात में वन मंत्री था, तब सन् 2000 में केन्द्र में एनडीए की सरकार थी और तब जनजातीय लोगों को 20,900 हेक्टेयर वनभूमि के अधिकार दिए गए थे। गुजरात के 3,335 आदिवासियों को 2,236 हेक्टेयर वनभूमि के अधिकार देने का प्रपोज़ल दिसम्बर 2005 में गुजरात सरकार द्वारा केन्द्र को भेजा गया था किन्तु एक साल के बाद उसका क्लीयरेंस अब भी नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इतनी भूमि आदिवासियों को देने के बाद भी गुजरात में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। इसलिए कुछ लोगों का जो यह दावा है कि इस बिल से पर्यावरण को नुकसान होगा, यह बात मैं नहीं मानता हूं। गुजरात में काग्रेस के कार्यकाल में एक एकड़ भूमि भी वनवासियों को नहीं दी गयी थी, यह मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। केन्द्र में जनजातियों के मामले के लिए अलग मंत्रालय बनाने में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल में जनजातियों को न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व दिलाने में, जनजाति के लोगों के लिए अलग आयोग गठित कराने में और अलग आर्थिक आयोग बनाने में बीजेपी अन्य सभी दलों से अग्रसर है। रिज़र्वेशन न होते हुए भी राज्य सभा में जनजाति को प्रतिनिधित्व देने में भी हमारा दल अग्रसर है। सन, 2004 में आदिवासियों द्वारा, 1993 तक जिस पर खेती की जा रही थी, ऐसी वनभूमि के अधिकार देने का निर्णय भी एनडीए सरकार ने ले लिया था, यह सर्वविदित है किन्तु नामदार सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने से उस पर अमल नहीं हो सका। उपसभापति महोदय, इसलिए यूपीए सरकार द्वारा जनजाति के लोगों के वनभूमि और वन पर के अधिकार के लिए जो यह बिल लाया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। हालांकि इस बिल से सदियों से गरीबी से जूझती और वनों में बसती आदिवासी जनता को मिलने वाले लाभों के बारे में इस समय कुछ कहना जल्दबाजी होगी, ऐसा मुझे लगता है। मान्यवर उपसभापति महोदय, इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ने से पता चला कि आज़ादी के छः दशक में से पांच दशक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को आज यह ज्ञान हो रहा है कि वनों में बस रह जनजाति के लोग और वन दोनों अभिन्न हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता है, जनजातियों के साथ अन्याय हुआ है, इत्यादि-इत्यादि। देरी से ही क्यों न हो, इस ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं आपके माध्यम से कांग्रेस का अभिवादन करता हूं और इस आशा के साथ Something is better than nothing. मैं इस बिल का पुनः स्वागत करता हूं। महोदय, भारत के मार्गदर्शक सिद्धांत की ओर मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें कहा है कि ...।

"That the State shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker sections of the society and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from all sorts of exploitation."

महोदय, मुझे आज अत्यंत खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि पचास-पचास साल सत्ता में रहने वाले देश के एक जिम्मेदार दल ने आदिवासियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोमोट करने में, संविधान के इस मार्गदर्शक सिद्धांत की और संविधान के अन्य प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई है। मैं जनजातियों के शोषण का बयान किन शब्दों में करूं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। शिक्षा के क्षेत्र में, देश में सबसे ज्यादा कौन पिछड़े लोग हैं, वे जनजाति के लोग हैं। देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों में सबसे ज्यादा लोग कौन हैं, वे आदिवासी लोग हैं। देश के अनेक नागरिकों की तुलना में सुविधाओं से वंचित लोग कौन हैं, वे आदिवासी लोग हैं। आजादी के साठ साल बाद, आदिवासियों की इस स्थिति के लिए बहुत से लोग जिम्मेदार हैं, परन्तु इसके लिए अगर कोई एक दल जिम्मेदार है, तो वह कांग्रेस है। देश का जागरुक आदिवासी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। महोदय, आज हमारे देश का आदिवासी, देश की इन रीतियों-नीतियों के कारण कांग्रेस से विमुख हो गया है। इस बिल के द्वारा फिर से आदिवासियों को फुसलाने का काम किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, परन्तु आज का आदिवासी यह समझता है कि भले ही संविधान में हमारे हितों व अधिकारों की बातें लिखी हैं लेकिन कांग्रेस की प्राथमिकता तो कुछ ऐसे लोगों के हितों के लिए है, जिनका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं हुआ है। महोदय, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इस बिल को JPC को रेफर किया गया था, सदन को यह भली-भांति ज्ञात है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिनकी JPC ने सिफारिश की थी और उनको सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उनमें से कुछ को फिर से लाने के लिए मैंने कुछ संशोधन रखे हैं। मैं उनकी चर्चा बाद में करूंगा, परन्तु समय के अभाव के कारण मैं मोटे तौर पर कुछ बातें पहले कहना चाहता हूं। यह वन भूमि और वनों पर अधिकार का मामला है। Forest Conservation Act or Wildlife Protection Act. के कई ऐसे प्रावधान हैं, जो इसमें बाधा बन सकते हैं। इसलिए Tribal Affairs Ministry, भले ही इसमें नोडल मिनिस्ट्री हो, Ministry of Environment and Forest के साथ तालमेल रखने के लिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक coordination agency रखी जाए, ताकि किसी भी प्रकार की बाधाएं खड़ी न हों और अनावश्यक संगत न हो। महोदय, सदियों तक forest cover रखने में आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और पेड़ों की खेती में भी उनको काफी अनुभव और ज्ञान है। अत: उनको दी जाने वाली भूमि पर ऐसे पेड़ों की खेती करने पर बल दिया जाए, जिससे आदिवासियों को निश्चित आमदनी मिले और भूमि व पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। मेरा यह कहना है कि पेड़ों की खेती करने वालों को पेड़ बड़ होने तक पर्यावरण संरक्षण सब्सिडी दी जानी चाजिए। यदि आदिवासियों को दी जाने वाली वन भूमि ढलान वाली होगी तो वह कम उपजाऊ

होगी। अत: अच्छी खेती के लिए अच्छे वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाने चाहिए, ताकि भूमि की उर्वरकता बढ़े और उत्पादन भी बढ़े। खेती के काम में आने वाले औजार, उर्वरक तथा बीज इत्यादि के लिए लोन, सब्सिडी का प्रबंध संतोषपूर्ण मात्रा में किया जाए, ताकि आदिवासी किसान किसी साहूकार के शोषण के शिकार न बनें। अनेक डैम बनते हैं, अनेक योजनाएं बनती हैं, लेकिन उनका ठीक से पुनर्वसन नहीं होता है। इस बिल में कुछ प्रावधान हैं, लेकिन पुनर्वसन के मामलों में व्यक्तिगत समूह की आजीविका के विषय में विधि द्वारा या भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के प्रावधानों की संतुष्टि होना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा एक सर्वग्राही नीति शीघ्रातिशीघ्र लागू होनी चाहिए, केवल पैकेज देने से काम नहीं चलेगा। हमारे देश में minor forest produces, के लिए भी कोई समान नीति नहीं हैं, यह नीति बननी चाहिए और कृषि उपज के विषय में जो minimum support price है, वैसी minimum support price भी MFP के लिए तय होनी चाहिए।

इस बिल की धारा 3 (2) के तहत् विकास कार्यों, स्कूल, अस्पताल, मार्ग निर्माण इत्यादि के लिए भूमि देने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। मैं समझता हूं कि विकास कार्यों में जो रुकावट आती थी, वह इससे दूर होगी और उसमें सुधार होगा। मैं इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। यदि इसमें भूमिहीनों के लिए सरकार की आवास योजना के तहत भूमि देने का प्रावधान किया जाएगा तो बेहतर होगा।

उपसभापति जी, मैंने जो संशोधन दिए हैं, मैं उनके बारे में थोड़ी बात करूंगा। पेज दो पर लाइन पच्चीस में जो संशोधन है, उसमें जे.पी.सी. ने अपनी रिपोर्ट में वनों की क्लोज प्रोक्सिमिटी में रहने वाले जनजाति के लोगों को इस बिल के दायरे में लाने के लिए कहा था। इन प्रॉक्सिमिटी वाले लोगों को सरकार ने बिल के दायरे से निकाल दिया है। प्रॉक्सिमिटी वाले बहुत से लोग वन भूमि पर खेती करते हैं और एम.एस.पी. इकट्ठा करके गुजारा करते हैं। इस बिल के दायरे से ऐसे लोगों को निकाला गया है, जिनकी संख्या, जिनकी तादात बहुत बड़ी है। अगर यदि ये लोग निकाले गए तो बहुत कम लोगों को इस बिल का लाभ मिल सकेगा।

[उपसभाध्यक्ष—(श्री संतोष बागड़ोदिया) पीठासीन हुए।]

मेरा दूसरा संशोधन, पेज दो पर, आखिरी लाइन 47 पर, एम०एस०पी० में फ्यूल, वुड, स्टोन को रखने की जे०पी०सी० की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। आजीविका के लिए फ्यूल, वुड और अपने उपयोग के लिए स्टोन्स और सैंड्स का समावेश एम०एस०पी० में होना चाहिए, जो कि बेसिक नीड्स हैं।

तीसरा संशोधन, पेज तीन, लाइन चौंतीस पर एम०एस०पी० का, वन में से बाहर निकालने के लिए ट्रांसपोर्ट शब्द जे०पी०सी० की सिफारिश से निकाल दिया गया है। उसे रख दिया गया होता तो

अच्छा था। अगर नहीं रखा जा सकता है तो ऐसी चीजें बाइसिकिल या हैंड कार से निकालने का प्रावधान होना चाहिए।

पेज आठ पर ओवर राइडिंग इफेक्ट्स का एक सेक्शन पंद्रह था, जिसकी सिफारिश जे.पी.सी. ने की थी, परंतु सरकार ने यह सेक्शन ही निकाल दिया है। जैसाकि मैंने आगे कहा है कि एफ॰सी॰ए॰ और wild लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इस बिल के अमल में बाधा बनता है। इस संशोधन के द्वारा मेरा यह निवेदन है कि अगर आदिवासियों के हितों के लिए हम सचमुच चिंतित हैं तो टकराव की स्थिति में इस बिल के प्रावधान को प्रिवेल करना चाहिए, नहीं तो इस बिल का उद्देश्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता। मैं इस संशोधन पर बल दूंगा। मैं आशा करता हूं कि जनजातियों के हित में मेरे इन संशोधनों और सुझावों को उचित स्थान मिलेगा। धन्यवाद।

SHRI NABAM REBIA (Arunachal Pradesh): Mr. Vice Chairman, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on this very important piece of legislation. At the outset, I would like to congratulate the hon. Minister of Tribal Affairs for having brought in this legislation, which was one of the commitments of our UPA Government.

Sir, before I go into the details of some aspects of the Bill, I would like to say that the addition of words 'traditional forest dwellers' is of slight confusion to me. Therefore, Sir, I hope that the hon. Minister, while giving the reply, after this debate in the House, will clarify and enlighten us on this issue. Sir, Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of our Republic pronounced 'Panchsheel' and, one of the principles of the 'Panchsheel' was to recognize and respect the tribal rights over land.

I think, this piece of legislation, is in the direction of fulfilment of the trend and the principles of Panchsheel, laid down by Pandit Nehru. Now again, before I go into the details of the Bill, I would like to draw the attention of the Chair, under article 244, clause 5 of the Constitution, which is applicable to Scheduled Areas, the Governors, by notification, can declare that any law passed by Parliament or the State Legislature can be declared null and void in a particular Scheduled Area by the Governor of that State. Therefore, the scheduled part does not apply to most of the North Eastern Region, and, I believe, it does not apply to any of the States of the North Eastern Region. But, which are the States where this provision applies? The hon. Minister will be able to enlighten us in that respect. So, it should not happen that we pass a Bill here and tomorrow a Governor will set it

aside and make it inapplicable in a particular Scheduled Area. That is a very important aspect. The people who drafted this piece of legislation, probably they have taken into account the Constitutional aspect of this legislation. With the passage of this Bill, the Village Council will have more responsibility to preserve forest resoruces with care. And the Bill seeks to give legal sanctions to traditional rights of tribal of the forest resources. And, here it includes the rights of the traditional forest dwellers. The tribal people have been dependent on forests since time immemorial for their survival and livelihood. In fact, in my State of Arunachal Pradesh, many of the people are still root-gatherers and fruit-gatherers. From there, you can understand how much we are dependent on forests. The forest mafia has been active all over the country. They have been exploiting the forest resources. Here, I would like to bring to your kind notice, Sir; the ban imposed by hon. Supreme Court on timber operation in the country was a blessing in disguise. It may have affected the economy of some of the States and some people, but I would say that that was a right move, a good move and a timely move in the right direction. Otherwise, there was a lot of exploitation of forest resources in many parts of the country, especially, in my region. More than 82 percent of the area of my State is under forest coverage. There is also an allegation that the political and bureaucratic nexus at the State level has been responsible for the deforestation. Now, this Bill will have the potential to protect the tribal and traditional forest dwellers from harassment by the forest officials and exploitation of the forest mafia. Now, the hon. Minister of Tribal Affairs belongs to the North-Eastern Region. I would like to draw his attention and would like to spell out some of my own apprehensions about the North-East Region.

He is very much aware of the fact that the influx problem of the North-Eastern region has threatened to change the demographic pattern of the region. The State of Arunachal Pradesh, of course, has certain statutes, like Bengal Eastern Frontier Regulation of 1872, Chin Hills Regulation of 1896 which give us some protection from this influx problem. But still, in our neighbouring States like Assam, the traditional indigenous people have almost been reduced to minority today. The impact of this influx is coming to the neighbouring State like Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland and all other States of the North-Eastern region. Now, our apprehension is, when you are giving to the traditional forest dwellers the right over forest

and its resources, whether this will cover those people also because these people have been settling over there for some time. In Assam, the process of identification and detection of illegal migrants is on. But in neighbouring States, especially in hilly States, people have taken shelter there. You have to clearly spell out and enlighten us what would be the fate of these people who are now illegally settling in those remote border States neighbouring Assam. Whether these people will have the right over the forest, and how are you going to identify or define whether they have the right or not? And how are you going to define whether they are illegal migrants or they are traditional forest dwellers? Can anybody give any explanation? Anyone settling over there, you will tell he was born and brought up there. His ancestors were there. He has been there for more than 5 generations, 10 generations. A lot of explanation could come. But, how are you going to solve this problem? This is the case in the State of Arunachal Pradesh also. Of course, now, these Chakmas and Hajams, some of them have been given the Indian citizenship right. But, let me tell you that more than 90 per cent of them are still having the refugee status, and they have not yet been given the citizenship right. They are occupying most of the forest areas of Arunachal Pradesh. How are you going to define them? Whether you are going to include them within the definition of traditional forest dwellers or not. What would be the fate of ths Hajams and Chakmas, who are also threatening to change the demographic pattern of this sensitive border State Arunachal Pradesh? This is a very, very sensitive issue. You have to enlighten us on this particular issue.

Now, regarding the land, the problem of the cultivable land and other things, even if Arunachal Pradesh is geographically the biggest State amongst all the States of the North-Eastern region, we have limited cultivable land. The problem is, all our cultivable land and plain areas have been occupied by the forest department and notified as reserved forest areas, and thereby, rendering the indigenous tribal people homeless and houseless. Even if they are living in the forests, they are not able to cultivate their own land. All lands are being declared as reserved forest areas by the forest department. There has been a demand from the people that this should be de-reserved. De-reservation process should be there. How are you going to solve this problem? Are you going to de-reserve the areas and give back these lands to the tribal people or not?

This is one of the clarifications which I would like to seek from you

We have been suggesting to the Forest Department to reserve those areas where cultivation is not possible. Secondly, you reserve those areas where WRC cannot be practised, and do plantation in those hilly areas. The tribal people are always prepared to go and occupy only those cultivable and plain areas. This is how we are deprived of the cultivable areas in a State like Arunachal Pradesh. Here also I want an assurance from the hon. Minister on how he is going to address this problem.

Now, there is no substitute for jhooming and shifting cultivation in a State like Arunachal Pradesh and in some other hili States of the North-Eastern Region. Even if we try to practise terracing cultivation, jhooming still has to be there. These are the traditional methods of cultivaion. Shifting cultivation has also to be there. I would like to know whether the indigenous Tribals would be allowed to practise their traditional method of cultivation or not.

There is one more thing on which I would like to be enlightened by the hon. Minister. I am not going to take much of the time of the House. I have raised certain specific issues on the status of the forest lands which are now under the occupation of the so-called refugees in the State of Arunachal Pradesh. Are you going to regularise those areas in the names of those people or are you going to give those lands to the indigenous Tribal people? That is number one.

Number two, I would like to know whether the reserve forest areas, which are under the Forest Department, will be de-reserved and whether those areas will be given back to the Tribal people of those areas so that they can do better cultivation.

Regarding the influx problem in the region, which is threatening the demographic pattern of the whole region, how are you going to solve it or what are you going to do about it? These are some of the clarifications which I want to seek from the hon. Minister.

I would like to know what you are going to do about the Scheduled Tribes under article 245 of the Constitution. These are certain issues to be clarified. There may be so many lacunae in the Bill. I am not going into it.

I thank you very much, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity to participate in this very important discussion. I, once again, congratulate the hon. Minister for bringing forward this piece of legislation.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE in the Chair.]

**श्री महेन्द्र मोहन** (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया।

The Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers का यह जो बिल है, विधेयक, 2006, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही विलम्ब से लाया गया विधेयक है। मैं इसके समर्थन में बोल रहा हूं, लेकिन मैं यह आशा करता हूं कि इन वन्य क्षेत्रों में आदिवासियों की और अनुसूचित जनजातियों की जो स्थितियां हैं, उन्हें किस प्रकार से सुधारा जा सकेगा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। केवल बिल बना देने से उनकी स्थितियां नहीं बदल जाएंगी, उन्हें हमें मेनस्ट्रीम में भी लाना होगा। हम उनको कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे करें, क्योंकि अगर हम इसके पुराने रिकार्ड पर जाते हैं, तो अंग्रेजी राज में आदिवासी नीतियों के विरोध में सन् 1700 से 1707 के बीच तिलका-मांझी, सिद्धू-कानू एवं बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया था। ये उस विद्रोह के चर्चित नाम हैं, परन्तु इनमें भागीदारी करने वाले हजारों-हजार गुमनाम आदिवासी थे। इस विद्रोह को कुचलने के दौरान अंग्रेजों ने भारत की अकूत वन-सम्पदा का सही रूप से पता लगाया। इसके साथ ही आदिवासियों से छीन कर उन्हें कमजोर करने के लिए और उन्हें विद्रोह की सजा देने के लिए तथा वनों के व्यवसायिक उपयोग के लिए वन विभाग की स्थापना की। पहला वन कानून, अपने सम्पूर्ण हित-साधक वन कानून को अंग्रेज़ों ने 1927 में बनाया। बाद में अंग्रेज तो चले गए, पर भारतीय वन कानून, 1927 आज भी लागू है और वन विभाग अपने ब्रिटिश पूर्वजों द्वारा सौंपे गए इस दायित्व को आज भी निभा रहा है और हमारे जितने भी आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो उन वनों में रह रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, उस शोषण को समाप्त किया जाना चाहिए। वहां पर कैसे शिक्षा बढ़े, कैसे उन्हें उनके हक मिलें, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम इस बिल को सही रूप से लागू करें और इसका सही रूप से इम्प्लिमेंटेशन हो। आजादी की लड़ाई के दौरान भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमान्त किसानों, उभरते हुए औद्योगिक मजदूर वर्ग एवं मध्यम वर्ग की मांगों को मान्यता मिली, किन्तु वन आधारित जीवन जीने वालों के शोषण, दमन एवं पीड़ा को इसमें शामिल नहीं किया गया। आज हम कहते हैं कि वन्य ही हमारा जीवन है, वनों के द्वारा ही हमारा पर्यावरण सही रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी वनों का जा दोहन हो रहा है, जिस प्रकार से पेड़ों को काटा जा रहा है, जिस प्रकार से इन जनजातियों की सम्पत्ति को छीना जा रहा है, उन्हें भूमि विहीन किया जा रहा है, यह बहुत ही गलत है और इसे रोकना हमाने लिए बहुत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह हमारे लिए और हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि इससे ऐसा एक आन्दोलन फिर से छिड़ेगा, जैसे आन्दोलन पहले हो चुके हैं। हमें देखना है कि हमारे वनवासी, जनजाति और आदिवासी लोगों को कैसे उनाक हक मिल, कैसे उनकी जमीनें उन्हें वापिस मिलें और कैसे वे लोग अपने कामों को आगे चलाएं। आज आदिवासियों के ऊपर

तरह-तरह के अन्याय हो रहे हैं और वनवासियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का बहुत समय से इंतजार था। यह कानून देश के लिए लाया गया है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन, कानून बना देने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि कानून का सही इम्प्लिमेंटेशन नहीं किया जाएगा। आजकल जो भी स्थितियां हैं, उनमें अधिकारी वर्ग बहुत ही गलत ढ़ंग से हमारे इन जनजाति के आदिवासियों के साथ व्यवहार करता है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि जिन परिस्थितियों में वन विभाग का ब्रिटिश राज्य में भूमि का सीमाकरण किया गया था, वह एकतरफा और अन्यायपूर्ण कार्यवाही थी, उसी के कारण अनेक आदिवासी, वनवासी समूहों के भूमि अधिकार खतरे में पड़ते चले गए। स्वतंत्रता के बाद भी कई बार ऐसी मनमानी हुई, यहां तक कि सरकार द्वारा आबंटित भूमि पर से भी यह कहकर परिवारों को खदेड़ दिया गया कि यह वन विभाग की जमीन है। इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जिससे कि हमारे उन जनजाति और आदिवासी, जो कि हमारा गरीब तबका है, जो हमारा पिछड़ा हुआ तबका है, उसको बहुत कष्ट पहुंचाया जाता है। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि आज भी हरिद्वार जिले के पुरुषोत्तम नगर के टौंगैया गांव में जाने पर लगता है कि जैसे किसी ने इस गांव में विकास न पहुंचने देने की कसम खा ली हो। यहां के लोगों के पूर्वजों ने कितनी ही वनभूमि को हरा-भरा किया था, पर आज इन गांववासियों को बुरी तरह से उपेक्षित हालत में छोड़ दिया गया है और वे उपेक्षित पड़े हैं। बच्चों के पढ़ने के लिए वहां पर एक भी स्कूल नहीं है। तो ये जो जनजाति के लिए जमीनें हैं, मैं प्रावधान देख रहा था कि उसमें यह भी प्रावधान रखा गया है कि सरकार के द्वारा इन वनवासियों की जमीनें लेकर वहां पर विद्यालय तथा ऐसी अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं। तो मैं आदरणीय मंत्री जी से यह जरूर कहना चाहूंगा कि यह जो प्रावधान है कि वहां पर स्कूल, औषद्यालय, आंगनवाड़ी, अस्पताल, उचित दर की दुकानें या अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं, उसके अंतर्गत यदि आप हमारे वनवासी, जनजाति के लोगों से जमीनें लेते हैं, तो आप वहां पर यह भी देखें कि उन स्कूलों में या वहां पर जो सुविधाएं दी जाएं, उनमें उन्हें थोड़ा सा रिज़र्वेशन मिले, उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलें, उनके लिए वहां पर विशेष व्यवस्थाएं की जाएं ताकि जिनसे जमीनें ली गई हैं, उनका लाभ उनको भी पहुंचे और उनका फायदा हो। उनका रिहेब्लिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, यह न हो कि उनको वहां से तो उजाड़ दिया जाए लेकिन उनके पास रहने की कोई व्यवस्था न हो और फिर ऐसी झुग्गी-झोंपड़ियों में वे रहें, जैसी हम यहां दिल्ली में और मुम्बई में देखते हैं और यहां पर भी उनका उत्पीड़न होता है। तो ये चीजें देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वहां पर इस प्रकार की चीजें न हों।

इसके साथ ही साथ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो संयुक्त समिति बनी थी अनुसूचित जनजाति वन्यचारों की मान्यता के बारे में, उसके प्रतिवेदन में एक बहुत ही खास बात लाई गई थी, जो मुझे इस बिल में नहीं दिखलाई दे रही है। समिति की रिपोर्ट के खंड 2(ग) में कहा गया है, एक रिकमेंडेशन थी कि समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने सूचित किया

कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की बड़ी संख्या न केवल वन में रहती है, बल्कि वह वनभूमि में लगे क्षेत्र में भी रहती है। "...जो मुख्यत: अपनी वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं के लिए वन पर आश्रित है। तथापि, वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान परिभाषा में अनुसूचित जनजातियों के वे समुदाय शामिल नहीं किए गए हैं, जो वन भूमि से सटे क्षेत्रों में रहते हैं। इस प्रकार उनके अधिकारों को मान्यता देने और अधिकारों को उनमें निहित करने के लिए अपने दावों से वंचित रह जाएंगे, जिससे उनकी आजीविका को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। समिति महसूस करती है कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा में ऐसी अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने के लिए व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है, जो वन भूमि से सटे क्षेत्र में रहती हैं, ताकि उनके आजीविका के अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा की जा सके।" तदनुसार, खंड 2 (ग) की परिभाषा को संशोधित किया गया है।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस पर विचार करें और इसमें उन लोगों को सम्मिलित करने का भी प्रयास करें, जिससे उन्हें भी ये सभी सुविधाएं मिल सकें। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान प्रधान मंत्री के उस आश्वासन की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें प्रधान मंत्री जी ने पर्यावरणविदों को आश्वासन दिया है कि "जनजाति भूमि अधिकार विधेयक" से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इससे जो सबसे गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है वह यह है कि कहीं ऐसा न हो कि जब सरकार के पास उन जमीनों को लेने के लिए अधिकार आ जाएं और वे वहां पर तमाम नई-नई चीजें बना सकें और इस कारण वे वहां से जमीने ले लें, जिससे पर्यावरण के ऊपर असर आए।

आज हमारे देश का पर्यावरण इसी तरह समाप्त होता जा रहा है। आज वह बहुत ही खराब स्थिति में है और वन सम्पदा के द्वारा ही हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि वहां पर जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग रह रहे हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें यह पूरा मौका दिया जाए कि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएं, कार्य के क्षेत्र में आगे आएं, उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए, उनका प्रापर रिहैबिलिटेशन किया जाए और इसके साथ ही साथ उन्हें वे सब अधिकार दिए जाएं, जो उन जमीनों के ऊपर उनके पूर्वजों के अधिकार रहे हैं। उनसे उन अधिकारों को छीना न जाए और उस जनजाति को बचाया जाए, क्योंकि जो हमारा कल्चरल हैरिटेज है, वह भी उन्हीं के द्वारा बना हुआ है।

आज भी हमारे बहुत से क्षेत्रों में आप यह पाते हैं, जब हम गणतंत्र दिवस की परेड करते हैं तो वहां पर जनजातियों के द्वारा हमें प्रदर्शन दिखाए जाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा उस हैरिटेज को बचाने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। हम उन्हें कैसे बचाएं और किस तरह उन्हें मेनस्ट्रीम में ला कर देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें?

इसी के साथ-साथ, मैं यही चाहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय इन बातों का ध्यान रखें और यह जो विस्थापन हो रहा है, उन्हें वहां से हटाया जा रहा है, उसकी जगह वहां पर रिहैबिलिटेशन के द्वारा इस काम को आगे बढ़ाने में योगदान दें। इन शब्दों के साथ, आदिवासियों की समस्याओं की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करवाते हुए, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि हमारी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकारों का जो बिल है, वह यहां पर पारित किया जाए, लेकिन साथ ही इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाए कि कैसे हम उन्हें मेनस्ट्रीम में लाएं और कैसे हम उन्हें देश का एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद दें। धन्यवाद।

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, it was his maiden speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): But he completed it within the allotted time. Now, Shrimati Brinda Karat.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, with a sense of great satisfaction and happiness, I stand, on behalf of my party, to extend our full support to the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Bill, 2006.

सर, मैं कहना चाहती हूं कि इस बिल के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। जब यह कहा जाता है कि हिस्टॉरिकल इन्जस्टिस को समाप्त करने के लिए यह बिल लाया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसी हिस्टॉरिकल इन्जस्टिस के खिलाफ हमारे लाखों-करोड़ों आदिवासी लड़े हैं। वे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़े और शहीद भी हुए, उनके संघर्षों और जबरदस्त योगदान के आधार पर हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन उस आजाद देश ने उन वन में रहने वाले आदिवासियों के जो न्यूनतम अधिकार थे, जो ब्रिटिश कोलोनिस्ट्स ने उनसे छीन लिए थे, वह न्यूनतम अधिकार आज भी वन आदिवासियों के हैं। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगी कि आदिवासी केवल वन पर निर्भर ही नहीं रहते हैं, बल्कि आदिवासियों के कारण ही आज वन बचे हुए हैं। इस हकीकत को छिपाकर हमारे आदिवासी भाई-बहनों से वह अन्याय चलता रहा और आज मैं यह कतई नहीं मानती हूं कि यह कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव से आया है। आज अगर यह बिल आया है तो यह आदिवासियों को श्रेय जाता है कि लाखों आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाकर संघर्ष किया और सैकड़ों की तादाद में कुर्बान हुए, और अब हिन्दुस्तान की संसद में स्वीकार करके इस बिल को लाए हैं। मैं यू.पी.ए. सरकार को, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर को, मिनिस्ट्री ऑफ एंवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के मंत्री को और विशेषकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मुखिया श्री प्रणब मुखर्जी को बधाई देना चाहती हूं कि तमाम लॉबीज और तमाम दबावों के बावजूद आज यह बिल आया है। जहां आदिवासियों का दबाव रहा है वहां आदिवासी विरोधी पर्यावरण का नाम लेने वाले, मैं उनके बारे में

ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं लेकिन आज कौन नहीं जानता कि एन्वॉयरमेंट के नाम पर या कंजरवेशन के नाम पर बिल्कुल गलत समझ के आधार पर आदिवासियों की उनके इस अधिकार से वंचित रखने की एक साजिश रची गई। फ्राइडे के दिन जब यह बिल लोक सभा में पारित हुआ, सर, मैं कल टेलीविजन देख रही थी, मैं रांची में थी, तो हजारों की तादाद में आदिवासी खुशी मना रहे थे इस बिल का समर्थन करते हुए और वहां टेलीविजन पर मैंने एक बहुत प्रसिद्ध वकील की बात सुनी और उन्होंने कहा कि पहला मेरा काम यह होगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर इस बिल को चेलेंज करने के लिए पिटिशन दर्ज करूंगा। यह सब का अधिकार है। लेकिन एक सवाल हमारे सदन के सामने है कि बार-बार उच्च न्यायालय संसद के उस समझ के आधार पर नहीं, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप किया और आदिवासियों को जंगल से खदेड़ने के इस प्रकार के आदेश दिए। हमारे एन.डी. ए. के साथी यहां बैठे हैं, उनको पता है उस अदालत के आधार पर 2002 में एक सर्क्यूलर निकाला गया, जिसमें कहा गया कि जो आदिवासी 1980 के बाद वन में रह रहे हैं उनको निकालना पड़ेगा। लगभग दो लाख आदिवासी और फॉरेस्ट ड्वेलर्स को हटाएंगे। उनकी क्या हालत है हम सब लोग समझ ही सकते हैं। आज भी एविक्शन की तलवार लाखों आदिवासियों के ऊपर है, लाखों ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के ऊपर है, क्योंकि आज भी वह जजमेंट, वह आदेश है। मैं समझती हूं कि यह बिल पारित करने के बाद ही कानून में जो विडम्बना की स्थिति है वह समाप्त होकर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी। महोदय, इस बिल में एक बात और जुड़ती है। इसके पीछे एक बड़ा जबर्दस्त संघर्ष रहा है, जैसा मैंने कहा है। जे.पी.सी. का जो पहला ड्राफ्ट आया था, जिसको यू.पी. ए. सरकार लाई थी, उस बिल को अगर ज्यों का त्यों माना जाता तो मुझे लगता है कि अन्याय को समाप्त करने के बजाए अन्याय और गहरा हो जाता। कौन से आदिवासी के पास सबूत है, क्या एविडेंस है, आपने 1980 का कट ऑफ डेट रख लिया था। आपने कहा कि फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट 1980 का इसके बाद जो भी है, तो आदिवासियों ने कहा कि हम कहां से सबूत लाएंगे? उन्होंने कहा कि क्या केवल ऑफेंस की रिपोर्ट के आधर पर सबूत होंगे। तो हमारी लेफ्ट पार्टी के बार-बार इसमें हस्तक्षेप करने के बाद हमने इसके बारे में तमाम नेताओं से बातचीत की, इस बातचीत में जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वे कोई 1980 को बदलने के लिए कोई तैयार नहीं थे। लेकिन जब एक सवाल आया कि अगर वे नहीं बदलेंगे तो यह बिल उस रूप में नहीं आ सकता है। तो जे.पी.सी. की उस सिफारिश को जो 1980 से 2005 की सिफारिश थी, उन्होंने स्वीकार किया, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि जो एक जबर्दस्त अन्याय होता, वह अन्याय रूक गया। सर, जो जबरदस्त अन्याय होता, वह अन्याय रूक गया। दूसरी बहुत गलत समझ थी, उस बिल में कि जो बाकी traditional forest dwellers हैं, उनके साथ नहीं जोड़ेंगे, तो हम क्या करना चाह रहे थे। जो परम्परागत रूप से वनों में रहते हैं, एक प्रदेश में एस.सी. है और दूसरे प्रदेश में एस.टी. है, कई जगह ब्रिटिश जमाने से फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए उनको या उनके इंटरेस्ट के

**7.00 P.M.**

जंगल में लगे, वे ट्रायबल नहीं थे, वे नॉन ट्रॉयबल एस.सी. हैं या और भी गरीब लोग हैं, लेकिन जो पहले बिल का ड्राफ्ट था, उसमें उनका नामोनिशान नहीं था। जब हम लोगों ने, लेफ्ट पार्टीज की तरफ से बहस की, तो हमें बताया गया कि हम दो बिल लायेंगे। एक बिल ट्रायबल्स के लिए और दूसरा नॉन ट्रॉयबल्स के लिए। हमने कहा कि आप वन के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर विभाजन करना चाह रहे हैं और हम यूनिटी की बात करना चाह रहे हैं। आप वहां अन्याय के बजाय एक को न्याय के नाम पर दूसरे पर अन्याय कर रहे हैं। आप उनको फॉरेट से हटाएंगे, तो पूरा सोशल अनरेस्ट होगा, आप इंटरनल सिक्योर्टी के बारे में सोच रहे हैं और वहां खुद इंटरनल सिक्योर्टी की समस्या पैदा करेंगे। हमने कहा कि गरीबों की यूनिटी को आप इस प्रकार से नहीं तोड़ सकते हैं, टू बिल थ्यौरी नहीं चल सकती है।

अभी इसमें जो जेपीसी की सिफारिश थी। इस बात को हम समझ रहे हैं कि एनक्रोचर्स को हम कोई लू-पोल नहीं देना चाहतें हैं। हमारे साथी ने नार्थ-ईस्ट की जायज चिंताओं को हमारे सामने रखा। जेपीसी ने इन तमाम सवालों पर गौर किया, पूरी बहस की। हम एनक्रोचर्स को कोई लू-पोल नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हमने कहा कि थ्री जेनरेशन्स जो फॉरेस्ट में रह रही हैं, वे एनक्रोचर्स नहीं होंगें आप थ्री जेनरेशन के आधार पर इसको रखिए। अब सरकार ने क्या किया? हमारा तीन जेनरेशन से अर्थ क्या था? हमने कहा कि जो ऐडल्ट क्लेमेंट्स, उनके पैरेंट्स और उनके ग्रैंड पैरेंट्स यानी की तीन जेनरेशन हैं, उनके कम से कम एक ग्रैंड पैरेंट्स वन में रहे हैं। इस प्रकार ये तीन जेनरेशन्स बनते हैं और इन तीन जेनरेशन्स के आधार पर आप उनको traditional forest dwellers मान लीजिए। यह बहुत लोजिकल और रीजनेबल चीज है। अभी सरकार ने इसका क्या किया? उसने 75 साल का लिख दिया। क्या 25 साल एक जेनरेशन के लिए यह कभी हो सकता है? किसके पास इसके बारे में सबूत है। आप 1930 पर जायेंगे उसके बाद कितने लोग फॉरेस्ट में आए और फॉरेस्ट का मतलब क्या है? सर, फॉरेस्ट का मतलब हमारी परिभाषा में यह है, इसको सुनकर आप हैरान होंगे, जहां ट्री कवर है, कोई भी जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फतवा राज से फॉरेस्ट डिक्लेयर हो सकती है। इस प्रकार सरकार के पास इतने डिटेल्स हैं, मैं इनके आंकड़ों में नहीं जा रही हूं, जहां पर ट्रीज नहीं हैं, लेकिन वहां भी फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। एक दिन अचानक वहां पर सालों से रहने वाले लोगों को पता चला कि अब यह फॉरेस्ट एरिया है, अगर उनके पास पट्टा है, तो पट्टे की स्वीकृति है या नहीं है, यह भी कुछ पता नहीं है।

अभी मैं आपको बताती हूं कि तीन साल में, 2001 से 2003 तक तथाकथित फॉरेस्ट एरिया 6.5 लाख बढ़ गया। जब मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा कि यह कैसे बढ़ गया। उन्होंने कहा कि यह तो स्टेट गवर्नमेंट के प्राविजन्स के मुताबिक उन्होंने बढ़ा दिया है। हमने पूछा कि कितने परिवार वहां पर रह रहे हैं? उन परिवारों का अधिकार स्वीकृत है या नहीं है? इसका कोई जवाब नहीं था। इसका

मतलब जो नॉन tribals traditional forest dwellers हैं, अगर इनके लिए थ्री जेनरेशन की, 75 साल की शर्त रखी जाती है, तो इनके साथ भारी अन्याय होगा। इसलिए मैंने इसके संबंध में एक संशोधन मूव किया है कि जेपीसी की जो स्प्रिट है, आप उसको रखिए। यूपीए सरकार के कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में लिखा हुआ है, "we will not affect tribals or traditional forest dwellers. It is your Common Minimum Programme."

इस कानून के बाद क्या आप उनको निकालेंगे? इसलिए मैं चाहती हूं कि जो थ्री जेनरेशन की परिभाषा है, इसको आपको बदलना है। आदरणीय मंत्री जी, इसके बारे में हमें कुछ स्पष्ट आश्वासन दें, यह मैं अपील करती हूं।

सर, इसके साथ-साथ दो-तीन सवाल और हैं। एक है - पिछले 50-60 सालों में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत फॉरेस्ट में सैटल्ड हुए हैं। अपनी मर्जी से नहीं, Srimavo Pact हुआ, श्रीलंका के लोग यहां आए, यहां रीपेट्रिएट होकर आए, तमिल लोग, उनको कहां रखा गया, तमिलनाडु के हिल्स में, बाद में उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया। उनका क्या होगा? बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए, उनको सेटल किया गया - गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत। तो जो आलरेडी सेटल्ड हैं, या गवर्नमेंट सरकुलर्स और आदेश के मुताबिक जिनके राइट्स गारेंटिड हो गए हैं, उनका क्या होगा? उनकी संख्या कम नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं, जेपीसी की रिकमेंडेशंस में यह बिल्कुल स्पष्ट था कि स्टेट पॉलिसी के तहत जिनको वहां सेटल किया या जिनके राइट्स गारेंटिड हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। श्री प्रणब मुखर्जी जो जीओएम के हेड हैं, इस बारे में जब बहस की तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस संबंध में निश्चित तौर से सरकार देखेगी और यह नहीं होने देंगे, उनके राइट्स को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूं कि सदन में हमारे आदरणीय मंत्री जी उसके बारे में स्पष्ट बताएं।

एक और बात इसमें है जो हमारे बिल से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अधिकारों के बारे में। अब यह माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है? हम जानते हैं कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कलेक्शन के लिए सबसे अधिक आदिवासी महिला शोषित होती है। मैं एक ही प्रदेश की आपको मिसाल देती हूं जहां लगभग 11,300 केस हैं - एक विशेष प्रदेश में—जहां सौ रुपए के नीचे फाइन्स हैं लेकिन उनको रोज कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। पिछले कई सालों से यह चल रहा है जो इस प्रकार के 11,300 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में है। मुझे खुशी है कि माइनर फॉरेस्ट प्राड्यूस का अधिकार दिया गया है लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो आज फ्यूल वुड, ईंधन के लिए लकड़ी—हमने जेपीसी में कहा, ईंधन के लिए लकड़ी अभी भी चुनने का उनको अधिकारी दो तो इसमें से काट दिया। हमने कहा कि पत्थर काट करके आदिवासी अपने मकान बनाते हैं, उसको काट दिया। हमने कहा कि वहां जो पानी होता है, जो मच्छी होती है, आदिवासी उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको काट दिया। क्या कारण है उसको काटने

का? इसलिए मैं चाहती हूं कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में एक बहुत मुख्य अधिकार इस बिल में रेखांकित हुआ है, इसमें आप कहीं कटौती मत कीजिए। रूल्स में या किसी भी तरह से आप इसमें जोड़ दीजिए। एक जो सबसे मुख्य सवाल है, वह यह है कि बेनिफिशरीज कौन आइडेंटीफाई करेगा, बेनिफिशरीज को कौन पहचानेगा, किसी भी एक्ट के तहत? आप जानते हैं कि 5वीं शेड्यूल के तहत ''पेसा'' ऑलरेडी है, ''पेसा'' कानून है। उस ''पेसा'' कानून के मुताबिक जो ग्राम सभा है, उनके अधिकार चिन्हित हो गए हैं। उनके अधिकारों में है कि 5वीं शेड्यूल्ड में जो भी अधिकार हैं, जो भी बेनिफिशरीज हैं, कौन तय करेगा? ग्राम सभा तय करेगी - यह निश्चित है, कानून में आ चुका है। मुख्य सवाल ग्राम सभा का है। आज कौन बेनिफिशरीज होंगे, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जज करेंगे जिन्होंने इतने सालों से आदिवासियों के अधिकारी नहीं दिए? क्या उनको आज यह संसद अधिकार देने जा रही है कि आप ही तय करोगे? जिन्होंने अपमान किया? जिन्होंने अन्याय किया? आज क्या हम उन्हीं को अधिकार देंगे कि आप तय करो? कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमने एक संशोधन किया कि लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज का प्रथम स्तर ग्राम सभा तय करेगी। उसका फाइनल डिसीजन अगर डिस्ट्रिक्ट कमेटी को आप दे रहे हैं, उसमें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि हैं, उनका सही मात्रा में, जिसमें महिलाएं भी हों सही मात्रा में उनका प्रतिनिधित्व हो, नहीं तो वे रहेंगे दो और दूसरे रहेंगे बीस। जो लिस्ट ग्राम सभी से आयी है, वह सब काटी जाएगी और जो वे चाहेंगे, वह होगा। यह अन्याय होगा। ''पेसा'' कानून के अंतर्गत जो ऑलरेडी अधिकार दिया गया है, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते। इस गलत काम में हम हिस्सेदार नहीं हो सकते कि जो कानून में अधिकार दिया गया है, वह समाप्त हो, उसमें हम कम से कम हिस्सेदार नहीं हो सकते और मेरे ख्याल में मंत्री जी भी इस बारे में जरूर बोलेंगे। सर, इसमें एक सवाल यह है और जैसा हम कहना चाह रहे थे और जैसा हमारे साथी ने भी कहा है कि वन के नजदीक जो जमीन है और जो लोग उस जमीन पर रहते हैं, जो minor forest produces के लिए वन में जाते हैं, क्या उनका अधिकार minor forest produces के लिए रहेगा या नहीं रहेगा? जो जंगल के आस-पास की जमीन है, उसकी क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, मंत्री जी निश्चित रूप से यह बताएं। क्योंकि जब JPC में बात हुई थी, तब हम सबने कहा था कि चाहे वे वन के अंदर रहते हैं या चाहे वन से थोड़ी दूरी पर रहते हैं, तो एक सवाल उठा था कि आप उसका कितना एरिया कहेंगे? proximity कौन सा एरिया है, तो उस पर काफी बहस हुई थी और किसी ने आठ मिलोमीटर कहा तो किसी ने दस किलोमीटर कहा था। फिर JPC इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि आप कोई किलोमीटर मत दीजिए, लेकिन आप अलग-अलग देखिए क्योंकि इस देश में इतनी असमानता है और सब चीजें बराबर नहीं हैं। इसलिए आपको वहां बैठकर कुछ तय करना पड़ेगा और सर, इसलिए आपको कुछ flexible रहना पड़ेगा। यह जो proximity का सवाल है, इस पर मंत्री जी निश्चित रूप से कुछ आश्वासन देंगे, इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करूंगी। महोदय, मैं आज उन सबको बधाई देती हूं, जिन्होंने आज लाखों आदिवासियों के अधिकारों को

सुनिश्चित किया है और इसके लिए कार्य किया है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देती हूं, JPC के उन सभी सदस्यों को बधाई देती हूं, जिन्होंने इस बिल को और मजबूत किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

DR. RADHAKANT NAYAK (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak. Sir, I rise to support the Bill wholeheartedly. I also support the amendments moved by hon. Brinda Karatji. Sir, I do not want to take much of your time or the time of the House. But I thought, maybe, some general issues I should raise. Before that I want to thank the hon. Minister, the hon. Prime Minister and the Chairperson of the UPA who have initiated this Bill during this current Session of the Parliament. I was also a Member of the JPC; therefore, I have gone through the Bill in its nitty-gritty. I thought that I would raise some of the issues while supporting the Bill wholeheartedly for the consideration of the Government, especially the hon. Minister who has taken so much interest to get this Bill passed in this Session.

Sir, you are aware that after the British Government went, we had a large number of issues to sort out especially the tribal problems and in the context of the tribal development. For the British Government, forest was a source of revenue. But for the first time after the independent Government came, they thought that this is also a source of rights or a source of livelihood for the people especially those who live in the forest areas. Sir, you are aware of Nehru's famous doctrine of Panchsheel in relation to tribal development. For reference and for recollection of this House, I thought I should read out these five principles which are very important. It says that the tribal people should develop along the lines of their own genius and we should avoid imposing anything on them. We should try to encourage in every way their own traditional arts and culture. This is number one. Second, the tribal rights in land and forests should be respected. It is a very, very important policy enunciation by Pt. Nehru himself. The third is that we should try to train and build up a team of their own people to do the work of administration and development. Some technical personnel from outside will, no doubt, be needed, especially in the beginning. But we should avoid introducing too many outsiders into tribal territory. The fourth is, we should not over-administer these areas or overwhelm them with the multiplicity of schemes. We should rather work through, and not in rivalry to, their own social and cultural institution. The fifth, Sir, is equally important.

We should judge results, not by statistics or the amount of money spent on tribal development but by the quality of human character that is evolved. Sir, if we very seriously reflect on the ethical, philosophical or legal dimensions of these doctrines, we have voilated each one of them with impunity. Although colonialism was over but the internal colonialism which was more rabid and yet very subtle that prevailed and till today it has been prevailing and it is in that context only, Sir, I thank the UPA Government, the Minister and the Ministry that they have taken some radical steps in order to introduce this Bill and also get it passed. Sir, these doctrines raise a number of issues. I will touch upon one or two of them only. Sir, the previous notion was, which has been already discussed, that the tribes are destroyers of forest. Actually, whatever forest today exists is only because of them despite the Government and the Government-supported or sponsored contractors. Sir, there are many other issues like shifting cultivation. One of our colleagues here raised this issue. Sir, in Orissa we have what is called a terrace cultivation which is on of the most scientific type of farming that the Sora tribes undertake, not to speak of other tribes in the North-Eastern areas also. So, there is so much of genius among the tribes, which we have ignored or we have neglected. There are so many other issues, Sir, the present trend in the globalisation or the Intellectual Property Rights are still looming large, which will definitely take away whatever rights the Government has been giving or will give now under this statute; they will take away and there may not be anything left even after that or later. Sir, some of the friends raised the ILO Convention of 107. Sir, I was a Member of the Indigenous People's Rights in the United Nations for some time. In a Committee, we found that every Government was supporting these conventions, the ILO 107. The latter one was ILO 169. These conventions are very, very important. One of the issues that were raised was self-certification or self-identification, which is very important. Today, Sir, a tribe in Orissa will not be considered as a tribe in Assam only because he needs a certificate from somebody else. But, the United Nations system now approves, the Indigenous People's Rights system, approves that a tribe once he declares himself a tribe, he remains a tribe. He doesn't need anybody's certification, anybody's inquiries, much less the RGI certification. That is what we were told in the last discussions. So my feeling is that, Sir, there is much to be done for enforcing the rights of the tribes and recognising the rights of the tribes which has been accorded or which has been accepted in the doctrine

enunciated by Pandit Nehru himself. Sir, there are a number of other issues, for example. Sir, we are yet to recognise in this country, by this Government, that the tribes are the indigenous people of this country. They were the first original Indians although some say that everybody is indigenous here. Yes, I don't question that. But some are more indigenous than the others. Therefore, in that logic, Sir, we must recognise the tribes or the indigenous people under the United Nations system.

Sir, by not recognising tribes as indigenous people, we are losing many of the programmes of the UN, UNESCO, ILO, UNICEF, World Bank, etc. Today, all these institutions want to do something for the tribal people. But, we are not taking those benefits to the tribal people. So, the Ministry and the Government should quickly recognise all the tribes as indigenous people which will be much better and help the tribal people to survive.

There are a number of other issues. The tribal people need a separate food and farming policy. As I said, the farming techniques, the slash-and-burn system of farming, which is available even today in Africa, helping many indigenous people to survive in those countries, are very, very scientific. The agriculture scientists have accepted that.

Similarly, we have many other indigenous medical systems which we have ignored. In this process we have destroyed not only health of tribals, their environment, but also the health of the entire country at large.

Sir, you are aware that the tribal people in this country are victims of large projects, big dams and industries. One of them was in Orissa. Very recently, 14 tribal people were killed in a cold-blooded manner. The hon. Prime Minister, Madam Sonia Gandhi, the hon. Minister had to go there and see how barbarous we can be against the tribal people. Therefore, today, the entire policy on tribal farming, tribal industries and tribal crops will have to be looked into again, not only to help the tribal people, but also to save this country from the verge of naxalite attacks. Today, we understand the naxalite problem only as a law-and-order problem. It is not true. It is not correct. It may be half-truth. We need to find out why a tribal boy or a girl becomes a naxalite. Unless we change our entire policy upside down, unless we have a fresh look at all our tribal development programmes, the naxalite problem or Mao problem will become a big menace. And, they will, ultimately, jeopardise our own Independence and freedom. Therefore, we need to, again, have a fresh examination of all our displacement and rehabilitation policies which affect only tribes, not other people. Of course,

other people also affected, but marginally.

Sir, without taking much time of the House and with these few words, I wish that allocation for tribal has to be enhanced. It has to be raised to a level where not only tribal people survive but also the entire country. Thank you.

श्री अवनि राय (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी और यू॰पी॰ए॰ सरकार को बधाई देता हूं कि इतने दिन के बाद एक ऐसा ऐतिहासिक बिल लाए हैं। इसमें वनवासियों को शिकार करते हुए, उनकी सुविधाएं प्राप्त करते हुए, जो बिल आपने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए और आपको बधाई देते हुए, दो चार शब्द इसमें कहूंगा। जब बात हुई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, बहुत दिन के बाद इन लोगों ने बैठकर, तय करके जो चीज आपके सामने रखी, उसमें से कुछ जगहों पर, जो बिल लोक सभा में पारित हुआ, उसमें कहीं-कहीं कुछ चीजों को छोड़ दिया गया। मैं इसके लिए मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा। जे॰पी॰सी॰ में कहा गया था कि सभी बातें मान ली हैं। हमारे पास ऐसी खबर थी। जब समन्वय समिति और बाकी जगह चर्चा हुई थी, तब भी हमें पता था ऐसा ही होना है। अब जहां-जहां कुछ छूट गया है, उसके लिए मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि उसे किसी भी रूप से इनके अंदर लाया जाए। यदि संभव हो तो आज ही इसे लाया जाए, नहीं तो जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, हम उससे थोड़ा पीछे हट जाएंगे। इसके साथ-साथ कुछ संशोधन के प्रस्ताव यहां पर लाए गए हैं, खास तौर से हमारी बहन वृंदा जी लाई हैं और श्री कांजीभाई पटेल साहब भी लाए हैं, मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं, फिर भी highlight करने के लिए कह रहा हूं कि जैसे पेज 2 पर लिखा हुआ है कि — 'primarily reside in' उसके नीचे 'or in close proximity of forests' को जोड़ दिया जाए। ऐसे ही वृंदा जी संशोधन लाई हैं। It is on page 2, line 47. I am not repeating this thing. I think it is already given to you. So, I am not going to repeat it. But, I will request the Minister to give some assurance on the floor of the House that the amendments moved by my colleagues, Shri Kanjibhai Patel and Shrimati Brinda Karat, will be accepted. Otherwise, the purpose for which we are bringing this Bill, that is, to safeguard the forest dwellers will not be a complete one. And the portions, which have been deleted, I would request you to consider them. I am not mentioning all these things again because all these things are known to you. I am not going to take much time on this because this is a Bill which we want, wholeheartedly, to be passed. And, since you have brought it, try to consider all the points. I think, the Minister will give an assurance on the floor of the House that he will accommodate all the amendments made by my colleagues and the portion which has been deleted at the time of passing in Lok Sabha will be

accommodated in the Bill. With these words, I congratulate the Minister. I congratulate the Government. Thank you everybody. At least, after a long time, the forest dwellers can enjoy something which the Government will give them.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Dr. Barun Mukherjee.

**श्रीमती सुषमा स्वराज** (मध्य प्रदेश): महोदय, सुशीला तिरिया जी को बोलना है।

**उपसभाध्यक्ष:** इनका नंबर बाद में है।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** कांग्रेस के बाद उनका नंबर आता है। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN: I have seen the list. Whatever list is given from the Table, I am following that. Dr. Barun Mukherjee.

DR. BARUN MUKHERJEE (West Bengal): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on this Bill. At the very outset, I must say that this is one such Bill or one such right of the forest dwellers for which we have been demanding for a pretty long time. It is commendable that, at last, this Bill has come. We feel that they are the most deprived group of people who have no right over the land on which they were dwelling for years together. That right is going to be established there with the help of this Bill. We welcome it and I support it on behalf of our party.

One thing which strikes me is this. I believe, at the fag end of the day, I should not take much more time, but one main thing that strikes me is regarding the establishment of the rights of the dwellers. It has been proposed that, firstly, the Gram Sabhas will certify about the rights of the particular forest dwellers. But, of course, from Gram Sabha it will go to the next committee, to the sub-divisional level committee, district level committee and it will go on. And, perhaps, as we have experienced over these appeals and hearings, it will be a very lengthy process.

If it happens to be a very lengthy process, one thing which must be ensured is that by that time the dwellers who are occupying the land must not be disturbed during this lengthy process. This has to be ensured; otherwise, there will be a lot of disturbances in the local areas of forests, where it occurs. Moreover, primarily, while seeking the advice of the

authorities of the *gram sabha* it appears that there is a scope for misuse of these things. Because, just now one hon. Member has referred to naxalite people. There may be some sort of prejudice about this while conferring the rights to the dwellers, in particular. The members of some *gram sabhas,* or the next sub-Committee, or the next sub-committee, may be prejudiced about it. So, there must be some mechanism so that it cannot be disturbed in any way. But, definitely, it is a good thing that there is a provision that the person concerned will have the right of hearing, before it is finally settled. But I think when this lengthy process is followed, some sort of mechanism should be there so that it may not be disturbed during that process. This should be ensured. Moreover, as regards the amendments, they have been elaborately dealt with by Shrimati Brinda Karat. I support the amendments moved by Shrimati Brinda Karat. I am not dealing with the amendment any more because the amendments have already been elaborately explained by her. As I said in the very beginning, I congratulate the hon. Minister concerned for bringing forward this Bill so that, atleast, after a long time the forest dwellers, the tribal people, will have their rights over the land on which they have been living for a pretty long time. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Shri Brahma' absent. Shri Syed Azeez Pasha.

SHRI SYED AZEEZ PASHA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the very outset, I want to congratulate the Government for bringing forward this Bill for consideration and passing. On behalf of the Communist Party of India, I rise here to support the Bill, but we are having certain suggestions to make. I hope that the Government will accommodate some of our suggestions and it will become a more perfect Bill. We are nearing to 60 years of our Independence. We are seeing that for the past 60 years, the tribal people who have been living in the forests are not the masters of forests. So, a lot of exploitation was going on. Several mafias were also exploiting. Therefore, after due consideration, the Government has come out with this comprehensive Bill. But, here, I would like to say that the Joint Parliamentary Committee, which is consisting of all political parties, has given certain recommendations unanimously. I don't know why the Government has not taken into consideration some of the positive suggestions given by the JPC. In this regard, I want to make two or three suggestions. I think, earlier also, some of our Members have already pointed

out them. Number one is regarding the generations. The proposal of the Government is 25 years. We think this is not proper. If we can reduce it to 12 or 15 years, that will be more perfect or the amendments given by Shrimati Brinda Karat can be accepted in this regard.

Sir, the tribal people who are residing there should be masters of all the produce which is there. Now, when there is a Pond, naturally they will go and catch it. If the Government says that they are going to be punished for that, this will be really unfair. To build their own dwelling, they will pick up some stones and do it, but, here, it is also becoming an offence as per the Bill. So, these sorts of undesirable things should be removed, and they should really become master of their own land. Sir, we think that due to the Government policies, some persons have long been settled in forest areas. Today, if we question it and if they do not get the same sort of rights, it will also be unfair. Now, another example of Narmada is also there where so many persons were uprooted. What about their future? Are we going to give any sort of guarantee to them or not?

Lastly, Sir, if we unnecessarily press them and ask about the title or *pattas*, naturally, they may not be having. So, any sort of oral evidence or some sort of affidavit should be sufficient to confer their ownership rights. So, these are some of the suggestions.

Sir, I feel that the hon. Minister would give a careful and positive thought to our suggestions which are given. Lastly, I say, we support all the amendments which are being moved by comrade Brinda Karat. Thank you very much for having given me this opportunity.

**सुश्री अनुसुइया उइके** (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा अति विलम्ब से, स्वतंत्रता के करीब 58 वर्षों के उपरान्त, अनुसूचित जनजातियों के लिए लाये गये "अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2006" का मैं स्वागत करती हूं। साथ ही माननीय सदस्या, श्रीमती वृंदा कारत जी ने जो सुझाव दिए, पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों पर अधिनियम 1996, जिसे पेसा कानून भी कहा जाता है, जिसमें जल, जंगल और जमीन से सम्बन्धित समुचित अधिकार आदिवासियों को दिये गये थे, उस संदर्भ में उन्होंने जो बहुत ही ठोस रूप में उन कानून को लागू करने की बात कही है तथा दूसरी बात कि पंचायत और प्रखण्ड स्तर पर जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा है, यह बहुत ही अच्छा है। उन्होंने केवल एक ही महिला का उन्होंने संदर्भ डाला, जब कि आदिवासियों में महिला और पुरुष दोनों ही समानता के साथ भागीदारी से श्रम करते हैं और कार्य करते हैं, इसलिए प्रतिनिधि भी उतने ही होने चाहिए।

मैं उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूं और उनका समर्थन भी करती हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहती हूं कि इस विधेयक की प्रस्तावना में एक बात कही गई है कि अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, जो वन पारिस्थितिक प्रणाली को बचाने के लिए और बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग है। यह एक बड़ा कटु सत्य है, जिसे सरकार ने स्वीकार किया है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं तथा देश और समाज को यह जानने का अधिकार है कि आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, तो माननीय मंत्री महोदय इस सदन में बताएं कि ऐतिहासिक अन्याय कौन-कौन से थे, जिनकी वजह से कौन-कौन लोग कब और कैसे प्रभावित हुए? क्या ऐतिहासिक अन्याय का अर्थ 3 करोड़ आदिवासियों का वानिकी और विकास योजना के नाम पर विस्थापन भी है? क्या ऐतिहासिक अन्याय का अर्थ 250 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों में बेदखल कर दिए गए लाखों वनवासियों की पीड़ा भी है? क्या ऐतिहासिक अन्याय का अर्थ सरदार सरोवर और टिहरी बांध से विस्थापित आदिवासियों को भूमिहीन कर देना भी है? क्या ऐतिहासिक अन्याय का अर्थ सामाजिक वानिकी और संयुक्त वन प्रबंधन के नाम पर देश में लाखों एकड़ सरकारी भूमि का छिन जाना भी है? क्या ऐतिहासिक अन्याय का अर्थ सन् 1974 के केन्द्र सरकार के आदेश के बावजूद आज तक लगभग 4,000 वनग्रामों को गुलाम बस्तियां बनाए रखना भी है? क्या ऐतिहासिक अन्याय का अर्थ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों में आदिवासियों पर दर्ज लगभग 11 लाख वन अपराध के प्रकरण भी हैं? क्या ऐतिहासिक अन्याय का अर्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में लाखों हैक्टेयर वन तथा सामुदायिक भूमि को उद्योगों के नाम पर हस्तांतरित करना भी है? सरकार सदन को यह भी बताए कि जंगल और जमीन से जुड़े किन-किन मुद्दों पर आदिवासी समाज के ऊपर क्या-क्या अन्याय हुए हैं और उन अन्यायों में किसकी क्या भूमिका रही है?

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यदि ऐतिहासिक अन्यायों के दायरे में यह सब शामिल है तो यह भी बताया जाना चाहिए कि आदिवासियों से संबंधित अधिकार विधेयक, 2006 इन अन्यायों से कैसे मुक्ति दिलाएगा और यदि ये वर्तमान बिल के दायरे में नहीं आते तो यह बताया जाना चाहिए कि इन मुद्दों को भारत सरकार आखिर आदिवासियों पर हुए ऐतिहासिक अन्याय क्यों नहीं मानती?

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि ऐतिहासिक अन्यायों का प्रथम दृष्टिकोण वैधानिक है, क्योंकि वन क्षेत्र में आदिवासी समाज को उनके अधिकारों से वंचित करने वाले प्रमुख कानूनों में केन्द्रीय वन संरक्षण कानून, 1980 के कारण आदिवासियों को उनके आजा-पुरखा से काबिज और संरक्षित भूमि पर खेती करने से वन विभाग द्वारा न सिर्फ रोका गया, बल्कि उन पर अतिक्रमण व वन अपराध के प्रकरण भी दर्ज किए गए। सभी आदिवासी बाहुल्य

क्षेत्रों में आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण न केवल वापिस लिए जाने चाहिए, बल्कि वन विभाग द्वारा की गई इस कार्यवाही के एवज में उन्हें मुआवजा भी दिया जाना चाहिए।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि आदिवासी समाज का मैं खुद भी प्रतिनिधित्व करती हूं, मैं भी उसी वर्ग की हूं, मैंने आदिवासियों के बीच में काम किया है, उनके दर्द को अच्छे तरीके से और करीब से समझा है और किस तरीके से उन पर अत्याचार होते हैं, मैं उसका एक उदाहरण यहां बताना चाहती हूं। रायपुर के बेमत्रा जिले में किस तरह से वन विभाग के अधिकारियों ने करीब 13 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा था। जब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग में थी, तो मैं स्वयं वहां पर इसकी जांच करने के लिए गई थी, मैंने पाया था कि बहुत बेरहमी के साथ उन महिलाओं को पीटा गया था। वास्तव में ऐसे कितने ही आदिवासियों को बेघर किया गया और इस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ।

**( श्री उपसभापति पीठासीन हुए)**

माननीय उपसभापति महोदय, मैं यह बताना चाहती हूं कि किस तरह से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के कारण विगत 100 वर्षों में आदिवासी समाज पर ऐतिहासिक अन्याय हुए हैं। आजादी के बाद बांध, खानिकी, उत्खनन, ऊर्जा परियोजनाओं और अब औद्योगीकरण के नाम पर आदिवासियों की भूमि पूरे देश में अधिग्रहित की जा रही है। चूंकि भूमि अर्जन कानून में आदिवासी ग्रामसभाओं और पंचायत के प्रस्ताव को वैधानिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई है, अतः इन परिस्थितियों में पूरे भारत में भूमि अर्जन कानून के कारण आदिवासियों पर ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। आज आवश्यक है कि इस अधिनियम में आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण को प्रतिबंधित करते हुए कड़े प्रावधान रखे जाएं। इसके साथ ही भारतीय संविधान में, जैसा कि श्रीमती वृंदा कारत जी ने कहा कि अधिनियम, 1996, जिसे पेसा कानून कहा जाता है, लागू किया गया। इस कानून की धारा 4(घ) में परम्परागत आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन संबंधित समुचित अधिकार सौंपे गए। इसी तरह भारतीय वन अधिनियम, 1927 लागू किया गया, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू किया गया। ये सब कानून बन कर रह गए और इन कानूनों से आदिवासियों को जितना अधिकार और संरक्षण मिलना चाहिए था, उतना प्राप्त नहीं हो सका है। माननीय मंत्री जी, इस विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं, वे कहीं पूर्व में जो अधिनियम बनाए गए हैं, उन्हीं की तरह कानून बन कर ही न रह जाएं, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

आज 58 वर्षों के बाद आदिवासियों के वनों में अधिकार के संबंध में बिल लाया गया है, जबकि 50 वर्षों तक केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन उन्हें इस बात का कभी ध्यान नहीं आया कि आदिवासियों के साथ किस तरह से अत्याचार, अन्याय और उनका शोषण हुआ है और आज इस

बात को उन्होंने भी इस विधेयक के माध्यम से स्वीकार किया है कि आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि जब माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी तो उन्होंने पहली बार आदिवासियों के दर्द को समझा और उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से विकास कैसे किया जाए तथा उनके साथ हो रहे अत्याचार से उन्हें कैसे मुक्ति दिलाई जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिए। सबसे पहले तो आदिवासी मंत्रालय, जो पहले होम डिपार्टमेंट के साथ था, फिर सामाजिक न्याय के साथ था, उन्होंने उसको अलग करवाया और साथ ही साथ आदिवासी मंत्रालय के ही द्वारा एनडीए की सरकार ने 270 जातियों को जनजातियों में शामिल करवाया। इसी तरह से आदिवासी आयोग को अलग करवाया गया, फाईनैंस कोऑपरेशन को भी अलग करवाया गया, साथ ही आदिवासी महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं का प्रावधान किया गया। एनडीए की सरकार में पूर्व प्रधान मंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा आदिवासियों का जो समुचित विकास हुआ और उनके अधिकार दिलाने के लिए जो कार्य किया गया, वह कांग्रेस के द्वारा 50 वर्षों में भी नहीं किया जा सका है। यह बात सिद्ध करती है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के विकास और उनके कल्याण की सोच रखती है। आज इस सदन के माध्यम से देश के लाखों-करोड़ों आदिवासी भाइयों की ओर से मैं तत्कालीन प्रधान मंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वापजेयी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं।

आज जब कांग्रेस सरकार को ऐसा लगने लगा कि उनका आदिवासियों का वोट बैंक घटने लगा है, तब सरकार के द्वारा अचानक जल्दबाज़ी में यह विधेयक लाया गया है।

महोदय, नये अधिनियम के संबंध में एक शंका मन में यह सता रही है कि वन्य जीव अधिनियम 1972, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 तथा जैव विविधता अधिनियम 2002 जो कि सभी वनों, वन्य पशुओं और अनुसूचित जनजाति से संबंधित रहे हैं, इनमें कोई ऐसे प्रावधान नहीं रहे थे, जिससे आदिवासी लोग जंगल से बेदखल हो जाएं, इसके बावजूद भी बड़ी बेरहमी के साथ वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें बेदखल किया गया और आज भी उन पर मुकदमें चलाए जा रहे हैं। कहीं नये अधिनियम की यह मंशा तो नहीं है कि जो आदिवासी वन क्षेत्रों में रह रहे हैं, वे अपने मूल अधिकार से ही वंचित हो जाएं।

यह सही है कि जब अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति जंगलों में निवास कर रहे थे, तब जंगलों का विस्तार हुआ है, इसके विपरीत जबकि आज वन संरक्षण के लिए कानून मौजूद है, तब भी निरंतर वनों का क्षेत्रफल घट रहा है। जब से अनुसूचित जनजातियों को जंगलों से, जिससे उन्हें रोजी-रोटी प्राप्त होती आई है, बेदखल किया गया है, तब से वन क्षेत्र कम हुए हैं। सदैव से ही न

सिर्फ वन तथा वन भूमि उनकी रोज़ी-रोटी का साधन रहे हैं, अपितु वे उसे अपना इष्टदेव, अपना रक्षक, जीवनदाता मानते हुए, उनकी रक्षा भी करते आये हैं, इसलिए वनक्षेत्र बढ़ता था। किन्तु जब से उन्हें वनक्षेत्र से बेदखल किया जाने लगा, तब से वन क्षेत्र भी घटना प्रारम्भ हो गया है, जो कि चिंता का विषय है।

वनों की रक्षा केवल वन विभाग ही नहीं करता, आदिवासी भी करता है। जिन वन क्षेत्रों में आदिवासियों का घनत्व अधिक है, वहां के जंगल आज भी सुरक्षित हैं। जिन जंगलों से आदिवासियों को बेदखल किया गया है, वहां की वन भूमि और वन्य जीवों को नुकसान हुआ है। इसलिए अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक 2006 में इस बात को जोड़ा जाए कि आदिवासियों से ही जंगलों की, वन्यजीवों की और पशुओं की सुरक्षा संभव है, क्योंकि यह उनके पैतृक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। जैसे मां से बेटे को अलग नहीं कर सकते हैं, वैसे ही जंगल से आदिवासियों को अलग नहीं किया जा सकता है।

महोदय, मैं एक और बात से भी आपको अवगत कराना चाहती हूं कि आदिवासियों में संग्रहण की प्रवृत्ति नहीं होती है, वे वनों से उतना ही लाभ लेते हैं, जो उनके जीवन के लिए आवश्यक होता है। अस्तु उनको वनों का संरक्षक समझा जाए, न कि उनका विरोधी।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इस विधेयक में कुछ संशोधनों पर सुझाव देना चाहती हूं। इसमें अध्याय एक में बिन्दु क्रमांक 2 के (2) (घ) और (च) में, जहां विधेयक की परिभाषा में वनभूमि तथा वनग्रामों का उल्लेख किया गया है, वनग्रामों के अंतर्गत वन कृषि बस्ती का उल्लेख किया गया है, इस परिभाषा में वन क्षेत्र में कृषि भूमि को भी परिभाषित किया जाना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव, बिन्दु क्रमांक 2 के अंतर्गत (2) (ज) में है, जहां वनांचलों में रहने वाले आदिवासी अपने रहने के लिए भवन निर्माण का कार्य भी नैसर्गिक स्रोतों से उपयुक्त रूप से करते हैं, अभी श्रीमती वृंदा जी ने भी इस संबंध में कहा है कि अगर वे मकान बनाना चाहें तो इसमें इस बात को परिभाषित नहीं किया गया कि उनमें लगने वाली रेत, मिट्टी, ईंट, कवेलू आदि का क्या प्रावधान हो, इसे परिभाषित किया जा कर प्रावधान में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

इसी तरह से बिन्दु क्रमांक 2 के (2) (झ) में मैं यह बताना चाहती हूं कि विभिन्न लघु वन उपज की परिभाषा के अन्तर्गत महुआ, चिरौंजी, बेर, हर्रा आदि का उल्लेख नहीं है, जबकि आदिवासियों के जीवन की मुख्य रूप से सबसे अधिक आधारित जो वन्य उपज हैं, वे हैं, महुआ, चिरौंजी, बेर हर्रा, लेकिन इसमें उनका कोई उल्लेख नहीं है। इन वस्तुओं का संकलन आदिवासियों द्वारा लघु वन्य उपज के तहत किया जाता है, अतः इन्हें भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए।

इसी तरह बिन्दु क्रमांक 3 के अंतर्गत (1) (क) में वन अधिकार के अंतर्गत वन क्षेत्र में रहने

वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए वैकल्पिक रोज़गार, स्वरोज़गार, व्यवसाय, पशु पालन आदि का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसका उल्लेख अवश्य ही किया जाना चाहिए क्योंकि ये कार्य उनकी जीविका के अनिवार्य स्रोत हैं। क्योंकि ये कार्य उनकी जीविका के अनिवार्य स्रोत है। इसी तरह बिन्दु क्रमांक-3(1)(ड) में आदिम जाति जनजाति समूह में नवगठित परिवारों को बसाने का प्रावधान भी जोड़ा जाए। राजस्व क्षेत्र में आबादी भूमि घोषित की जाती है। इसी तरह वन क्षेत्र में नये आदिवासी परिवारों के लिए प्रावधान रखा जाए। बिन्दु क्रमांक-3(2) के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों में वन भूमि ''क'' से ''ड'' तक जो आपने प्रावधान रखे हैं उनका तो मैं स्वागत करती हूं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। उसके साथ-साथ मैं इसमें एक और चीज शामिल करना चाहती हूं कि आपने स्कूल तो रखा है। कभी जब यह बात आएगी तो केवल स्कूल के बदले में मैं चाहती हूं कि उसमें शैक्षणिक संस्थाओं का प्रावधान हो, जिसमें शिक्षा से संबंधित और भी कुछ चीजें वहां पर प्रारम्भ की जा सकती हैं। इसके साथ आपने आवास के लिए कुछ नहीं कहा। सरकार के द्वारा जो इंदिरा आवास योजना की व्यवस्था है वह उनसे वंचित हो जाएगी इसलिए वहां पर इंदिरा आवास योजना का भी प्रावधान रखा जाना चाहिए। साथ ही आपने सुरक्षा के लिए पुलिस का भी जिक्र नहीं किया है। ये मेरा अपना सुझाव है कि उसमें पुलिस का भी प्रावधान किया जाए। इसी के साथ अध्याय-4 में जो वन अधिकार को निहित करने के लिए प्राधिकारी और प्रक्रिया है, उसमें सैक्शन-6(7) के अन्तर्गत मैं कहना चाहती हूं कि जो राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा उसमें आपने कहीं किसी तरह का संदर्भ नहीं दिया कि कैसे कमेटी गठित होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम 15 से 20 सदस्य हों जिसमें दो सांसद एक राज्य सभा से और एक लोक सभा के हों जो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सांसद हों तथा सामाजिक कार्यकर्ता, विशेषज्ञ, कानूनी सलाहकार भी हों। इस तरह से राज्य स्तरीय कमेटी का गठन होना चाहिए। इसी तरह से बिन्दु क्रमांक-6(8) में आपने जिला स्तर पर भी राजस्व, ट्राइबल डिपार्टमेंट और पंचायत के प्रतिनिधि को शामिल किया है। इसमें मेरा सुझाव है कि इसमें आपने पुलिस विभाग को नहीं रखा है। अत: इसमें पुलिस को भी रखा जाए। जिला अभियोजन अधिकारी, जिला लिधिक अधिकारी के साथ ही साथ क्षेत्र के दो प्रतिनिधि हों। इस तरह से यह कमेटी बनाई जाए और विशेष तौर पर वनांचलों में ग्रामीण स्तर पर। समिति में जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए वह संवैधानिक और लोकतंत्रीय पद्धति से जुड़ी हुई हो जिससे व्यक्ति विशेष का अधिकार न रहे और सामाजिक सरोकार की रक्षा की जा सके। यह प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। इसी तरह से एक और बात महत्वपूर्ण है तथा अध्याय-5 में अपराध और शास्तियों के संदर्भ में मेरा यह कहना है कि आपने एक हजार रुपए के दंड का प्रावधान रखा है। सभापति महादेय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि वह आदिवासी जिसको दो टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता उसके लिए आप एक हजार रुपए जुर्माने की बात कर रहे हैं। तो इसको कम करके कम से कम सौ रुपए का प्रावधान रखा जाना चाहिए ताकि वह व्यक्ति इस जुर्माने को सह सके।

इसके साथ ही मैं कुछ अन्य सुझाव भी देना चाहती हूं। इस विधेयक को लागू करते समय हमें कुछ ऐसी व्यवस्था तथा प्रावधान करना अति आवश्यक है कि इसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो, इसे क्रियान्वित करने वाले तंत्र के जिम्मेदार अधिकारी इस विधेयक की भावना के अनुरूप पूरी ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता, बिना किसी भेदभाव के सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे क्रियान्वित करें। इसके लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वन्य जीवों की रक्षा और वनों की रक्षा के लिए जो प्रशासनिक तंत्र जिला स्तर पर है, उसमें 50 प्रतिशत पद आदिवासियों के लिए होने चाहिए ताकि वे वनों की रक्षा कर सकें। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहती हूं कि पूरे देश भर में 75 प्रिमिटिव ट्राइब्स भारत सरकार ने घोषित किए, जो मूल रूप से सदियों से जंगल में निवास करते आए हैं और कंद-मूल, फूल पर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसी पिछड़ी जनजाति के लोगों के लिए इस विधेयक में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। अच्छा होता कि इस विधेयक में इनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किया जाता। इसके लिए मेरा विशेष तौर पर माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि नियम बनाते समय इनके परम्परागत अधिकारों को भी लिपिबद्ध किया जाए।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि यह देर से आया लेकिन यह बहुत अच्छा है और आपने आदिवासियों की जो परम्परागत, उनके अधिकारों के बारे में जो 2006 का बिल लाए हैं, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आदिवासी भाइयों की ओर से भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

SHRI B.S. GNANADESIKAN (Tamil Nadu): Thank you, Sir. I rise to support the Bill. There are two things. One is, after our Government came to power, it has shown that it has the will to make several enactments, particularly, regarding the rural employment guarantee, domestic violence, child rights, equal status for women by amending the Hindu Succession Act, then, only two hours before we have passed 27 per cent reservation to OBCs and now this forest Bill. Therefore, Sir, I congratulate this Government for brining in this Bill to protect the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers. As far as this Bill is concerned, there are four aspects. One is vesting the right; second is protection from eviction; third is upgrading their livelihood which is guaranteed under clause 3, and then, fourth is to use the home products. I congratulate the hon. Minister because this Government has the courage to admit that there is a historical injustice done. And, to my knowledge, this is the first time, in a legislative enactment, the Government admits that injustice has been done to a particular group or community and that injustice has to be remedied. Therefore, this Bill is being brought before this House. Therefore, this courage and wisdom has to be congratulated. Sir, there are two things.

8.00 P.M.

The nature of evidence is more important, as my respectable colleague Brindaji said, and as one advocate has mentioned that he was going to the Supreme Court regarding this Bill as it is being passed in the Lok Sabha. The evidence part of it will create a lot of confusion. It will give a lot of interpretation to the lawyers and it will give a scope for the judicial interpretation by exercising the judicial review. Therefore, Sir, the Act does not contain what are the proofs required to confirm the vesting of rights on the Scheduled Tribes and also the traditional forest dwellers. It is left to the rule making power. So, I think, it is better—the JPC also suggested—that the proofs required are elaborated and catalogued in the main section itself, so that there is no ambiguilty on this aspect.

Then, Sir, the Gram Sabha has to now pass a resolution. It has to be sent to the sub-divisional Committee. Then, it goes to the district-level committee. Sir, we know how these district-level committees, sub-divisional committees and revenue authorities are functioning. Therefore, instead of making these people to make the claim and verification and codification under the relevant section, is it not better, through you, I would like to ask the hon. Minister, that the Gram Sabha by itself can adopt some model or some method for verification as to who are the dwellers and *suo motu* they can go and verify? Because in this country, they also fought for freedom. They have been applying for several years for getting the freedom fighters' pension. But they are from running pillar to post. Likewise, these tribal people, who are innocent people, who do not understand the necessity and other things of modern society, have been put to very great difficulty, if they are asked to go to the sub-divisional committees and district-level committees.

Sir, there are two-three things which require some clarification from the hon. Minister. One thing is, under clause 6 (8), several departments have been included. Is it not better that the Law Department is also included as one of the authorities in the Committee so that the legal aspects can be considered? In clause 14 (b), a form has to be prescribed for clause 6 (2). But for filing a petition to the district-level committee, under clause 6 (4), no form has been prescribed. There is a lacuna in it and I request you to kindly pay attention to that aspect.

Sir, another aspect is, there is a time limit prescribed for courts to

interfere under clause 8. If you kindly see clause 8, it says, no court shall take cognizance of any offence etc. etc. through a resolution against higher authority not less than sixty days to the State Level Monitoring Committee. What is the time limit for the State Level Monitoring Committee for disposing of that resolution? On the 61st day,a person can go to court. So, that is another lacuna subject to correction. It has to be corrected.

Sir, similarly, I have mentioned clause 14(b). Sir, many people and hon. Members are saying that courts are interfering. Courts are interfering mostly because of certain lacunas in drafting of these enactments. On Assam Rifles Bill also, I found out certain lacunas in drafting of the Bill. Sir, my whip is already giving me the directions and I will obey my Whip. Therefore, Sir, I request that concentration should be made in drafting the Bill. If there is lacuna in the drafting of the Bill, courts have a scope of interference. Sir, one of the suggestions by the JPC is to put this Bill in the Ninth Schedule after it becomes an Act, to save it from being challenged in a court of law. Therefore, Sir, I request that this has to be done.

One more aspect is, kindly have some monitoring agency, find out the working of this Bill in the tribal areas, find out what are the lacunas and deficiencies and in the next Budget Session come out with the necessary amendments to rectify this. Sir, please allow me for only one minute. Sir, regarding Shrimati Brindaji's amendments, I support most of the amendments. But on one amendment, Sir, I have a reservation and if I am permitted, I would make an amendment to the amendment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have not given that amendment to amendment.

SHRI B.S. GNANADESIKAN: Sir, I will find out. I think my friends will also agree. Sir, clause 4 says, any others who have been settled in forest area by the Government policy. Sir, the settlement by the Government must be the uprooted Scheduled Tribes or the traditional forest dwellers. If it is not, there will be a problem. In our State many Sri Lankans have been settling in hilly areas. Many Sri Lankans have been settling in Kodaikanal hills, Yelagiri hills, etc. etc. They are not the traditional forest tribals.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Are they citizens of India? Then, don't bring them into this.

SHRI B.S. GNANADESIKAN: No, no. They are citizens because there are origins. Tamil origins are two - one is, Indian origin who went to

Sri Lankan and who have been sent back, they are the refugees. There are other type of refugees who are Sri Lankan citizens who have come to India and getting a refugee status. Therefore, we should not mix both. We must be careful on security scenario. Sir, we should not forget Mr. Veerappan lived in the forest for forty years in Tamil Nadu doing all types of mischief. He also did not ask for vesting the right in forest area. thank you, Sir.

SHRIMATI BRINDA KARAT: I cannot accept his amendment to my amendment.

**श्री उपसभापति:** श्री मंगनी लाल मंडल। मंडल जी, आप कुछ बोलेंगे?

**श्री मंगनी लाल मंडल** (बिहार): महोदय, मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सर, मैं माफी चाहता हूं कि मैं बीच में चला गया था, मेरा नाम बुलाया गया था।

**श्री उपसभापति:** आप सपोर्ट कर दीजिए।

**श्री मंगनी लाल मंडल:** मैं सपोर्ट कर दूंगा। महोदय, जो संयुक्त संसदीय समिति बनी थी, मैं उसका सदस्य था। मैं माननीय वृंदा कारत जी का भाषण सुनना चाहता था, संयोग से नही सुन सका किन्तु समिति में मैं इनकी सक्रियता देखता था। मैं किसी-किसी मीटिंग में नही रहता था लेकिन वृंदा जी आदिवासियों के मामले में काफी सक्रिय रहती थीं। मैं समझता हूं कि उनकी जो प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट है, उसी भाषण आलोक में उन्होंने दिया होगा, मैं अक्षरश: उसका समर्थन करता हूं और अपनी ओर से केवल दो बातें कहना चाहता हूं। महेन्द्र मोहन जी यहां नहीं हैं, मैं सुन रहा था कि तिलका माझी जी का उल्लेख उन्होंने अपने भाषण में किया था। तिलका माझी जी के नाम पर हमारे यहां बिहार में लालू जी ने विश्वविद्यालय बनाया, लेकिन जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में तिलका माझी ने अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया था, वनवासियों और आदिवासियों का संगठन बनाकर, वह क्षेत्र अब झारखंड में चला गया है। दूसरे आदिवासियों के नेता थे - बिरसा मुंडा, जिनको लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। दो महान नेता स्वतंत्रता संग्राम के हुए। लेकिन पर्यावरण के नाम पर 1980 में जो अधिनियम बना, वन संरक्षण अधिनियम, उसके द्वारा वनवासियों और आदिवासियों की दुर्गति हुई कि जलावन की लकड़ी के लिए तो वे प्रताड़ित किए गए लेकिन इसके विपरीत लकड़ी के तस्करों का एक माफिया गिरोह पैदा हो गया। हमने देखा है कि समिति ने जो सिफारिश की है, विधेयक में उसका समावेश किया गया है। जंगल की पेरीफरी में जो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, उनके लिए कुछ बिंदुओं पर प्रश्न था। संविधान बनने के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स हुआ। उसमें जो वनवासी हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए। कट ऑफ डेट के बारे में था। उसे भी शामिल किया गया है। उनके कल्याण के लिए जो विद्यालय बनाया जाएगा, उसमें कितने पेड़ कटेंगे, कमेटी ने

इसके लिए सारे सुझाव दिए हैं। संसदीय समिति ने व्यापक सुझाव दिए हैं। मैं समझता हूं कि सरकार ने बहुत सी अनुशंसाओं को स्वीकार किया है। यह विधेयक अपने आप में पूर्ण है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री उपसभापति:** श्री भागीरथी माझी। क्या आप बोलेंगे।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** उनका मेडन स्पीच है।

**श्री उपसभापति:** मेडन स्पीच है।

**श्री एस.एस. अहलुवालिया** (झारखंड): आप जो ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं। ओरिजिनल ट्राइब्स हैं माझी।

SHRI BHAGIRATHI MAJHI (Orissa): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Bill which provides to recognise and vest the forest right and occupation in forest land for the forget dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for generations. Sir, we are talking about the nation's building, nation's development, nation's strength, but it is not possible without the development of the tribals. We have to bring them to the mainstream of the nation, we have to work together, only then the nation will be strengthened. It was felt and realised by the then NDA Government, and for the first time after Independence of India, a separate Ministry of Tribal Affairs was created to safeguard the hopes and aspirations of the tribals, which constitute 9 pet cent of the country's population.

Sir, the NDA Government had done a lot for protecting the interest of the tribals. A separate S.T. Commission, an S.T. Financial Development Corporation were created. New States like Jharkhand and Chhattisgarh were created where there is a sizeable tribal population. I am happy to state that Santhali language was also adopted in the Eighth Schedule of the Constitution. Sir, I am happy to note that after 59 years of country's Independence, the long-standing demand of the tribals is going to be fulfulled with regard to their rights to the land on which they have been living for generations. Forests are an integral part of our tribal life. They earn their livelihood from forests. They are a part and parcel of the Indian forests life.

Sir, with your permission, I would like to submit a few points for the consideration of the hon. Minister. I want that the Minister should assure

us that the tribals will have access to the use of fuel to be collected from the forest. The tribals also should be allowed to renovate and construct his cottage by the wood collected from the forests. I would also like the hon. Minister to assure us that the place of worship of the tribals called "Jahira" mainly of Santhal tribes of Orissa, Jharkhand, West Bengal and Assam should be protected when some development activities like construction of dams and industry take place in the areas surrounding the forest.

Sir, just providing the right to forest land to the Tribals is not enough. The Tribals should be allowed to use the underground water by digging wells and tube-wells. The Tribals should be granted bank loans to undertake the irrigation activities. The banks should also provide the Tribals house-building loans to help them to construct their small houses. Then only will this Bill achieve its objective of providing a respectable shelter to the Tribal people of India.

Sir, I would like to bring to the notice of the hon. Minister that, in the past, many Tribals belonging to the Santhal community had migrated to Assam to work as labourers in the tea-gardens. It is unfortunate that these migrant labourers have not been recognised as Scheduled Tribes. The same is the story of the Tribals from the then undivided Bihar and Orissa, who were taken to the Andaman Nicobar Island as labourers for infrastructure development activities, and they have also not been recognised as Tribals.

While concluding my speech, I would like to thank Members and the Chairman of the Joint Committee which has done a commendable job by providing a ray of hope to the most disadvantaged section of the society.

Sir, I wish to further request the hon. Minister that the Notification of the implementation of this Act should be done at the earliest, unlike the PESA of 1996 which was implemented by the NDA Government, though it was passed in the year, 1996. Thank you.

SHRI P.R. KYNDIAH: Mr. Deputy Chairman, at the outset, I would like to express my grateful thanks to the hon. Members who have participated in the debate and also to vest rights in the forest dwelling Tribals and other forest dwellers who are traditional dwellers in the forest. They have been living there for ages; since time immemorial they have been living there at some places. I know of certain forest dwelling Tribals living there for centuries. I had an experience in Orissa. When I had been to Kalinga

Nagar, I came to know that they have been living there since 1862, not to speak of my own tribe which had come thousands of years ago. They are the orininal dwellers and they live in their own habitat, in the ancestral lands. Yet, somehow, during the consolidation of the State forests, their rights were not recognised. This Bill wants to vest rights on these people, this wretched segment of population. But when the rights were given, their rights were not undone. Therefore, we want to undo this historical injustice. Now what has happened to these people? This Bill, apart from being a landmark Bill, it is a historic Bill and it will undo the histrocial injustice. I think one of the speakers has mentioned what type of injustice that has been perpetrated on them. We know for a fact, in the forest area, where they dwell, they do not have any facilities. Their only mode of livelihood is dependent on the minor forest produce. They do not know what the civilization is. They have not tasted the fruits of civilisation. They are voiceless, unseen and unsung. If there is a segment of population which was described or reported as a folk, these are the people. They are the most deprived of the deprived. They do not come under the category of BPL. They are poverty personified. They represent the face of poverty in its worst form. These are the people for whom we have a mission to bring relief and save them from harassment. They are treated as encroachers. They were thrown out of their habitats. I know it. I would not like to name the place. The forest administration, in certain areas, used even the Ex-servicemen in order to torture them and take over the land that they occupied. It is pathetic. They were and they are the original dwellers of this land. They have suffered these miseries. It is miserable. Now, I am happy that a mention was made by one of the speakers about the first Prime Minister of this great country. I refer to Pt. Jawaharlal Nehru. He was the first person to recognise that these tribal people living in the forests are very important. There is the Nehruvian Panchasheel doctrine. There are two very important points which I will just repeat and read out to you. Development of tribal people along the life of their genes. I would like to say that you cannot put all the tribal people into one cultural basket. There is so much diversity, whether you speak of the North or the Sourth or the East or the mainland or the heartland. But more important is the purpose of this Bill that we are going to pass - I hope it will be passed - is the recognition of tribal right in land and forests. Pt. Nehru saw it in his vision. In fact, I will tell you a very simple story, a fact. He came to my place, Shillong, the then capital of the North East. I was a young Congress

leader. I met him. At that time, the word 'tribe' was not used really. My community, the tribal community, was of 3.5 lakh people. Pt Nehru described us as a microscopic minority, maybe, our population was not coming up, maybe, stagnant, maybe, a little below the level and today, becase of Pt. Nehru, we are 14 lakh people. I come from that community, the Khasi community. I come from that community where we have a multilingual society where women are already liberated. They need not be liberated. My name can be from the name of my mother, the clan of my mother, not my father's. It is not my father's name. And, it is because of Panditji, we are here today. At that time we were faced with three movements. One movement was to join with Pakistan because Mizoram did not exist earlier. Mohd. Jinnah was ailing at Shillong, the then capital of East Pakistan. The other movement was to join the British colony. The third one was to join India. I was interested in the discussion; even though I was young, a teenager, yet, I understood the problem. If we had looked at it economically, it could have been better for us to be with Pakistan. But we did not, because Panditji was there. He was the champion of the deprived. Right from day one we know about his passion with the North-East. At that time, it was NEFA; today you call it Mizoram. It was not for vote bank, but it was with a vision that India constituted all kinds of people, and smaller people must be taken care of. Here, I am today because of that heritage. In fact, if you ask me who my mentor is, I would say, Panditji. I love his socialistic pattern of society. I love his thinking of the poor people. He talked about independence of India, and he promised that in an independent India every small people, small community, must have a place under the Sun. And here I am! I am just sharing with you my experience. Now, we are also forest dwellers; we also come from forest areas. We live together with animals in jungles. At that time, Panditji said those words, and I am very happy that I happen to pilot this Bill now. I must thank the Prime Minister, Dr. Manmohan Singhji , for selecting the Tribal Affairs Ministry to pilot the Bill. In January 2005, this idea was mooted, and since the last two years, we have had extensive discussions; we have had a lot of seminars on the subject of Tribals Bill or the Forest Bill, as we call it now. And, is in the limelight of national media. I was happy that even though we had differences, we have been able to harmonise our differences, and today we come to this House having the support of all the parties. I must confess that. At every crucial stage, when the idea of Tribal Bill was mooted, it was none other than the Chairperson of the UPA, Soniaji, who

inspired me. Even while she was the Chairperson of the National Advisory Council, we had crucial discussions, and we intervened, again and again, to see to it that this comes in this fashion. It is something great and I will be failing in my duty, if I do not mention our former Prime Minister, Rajivji. I like his words. He said these words, " Immediately after the attainment of Independence, it was Pandit Jawaharlal Nehru who fully comprehended the problems of the *adivasis*. Ever since I became the Prime Minister, I have always devoted my attention to the *adivasis*, like Panditji and Indiraji". Again in a speech in 1986, he said, "If we want to save India, if we want to eradicate poverty, it is natural for us to protect the environment in every way. It is often thought that the poor, the *adivasis*, cut down the forests every now and then, and the Government" - he was the Prime Minister -- "comes down on them with a heavy hand. But the *adivasis* have been living in close pronimity of the forests for thousands of years. And the forests have not been destroyed; they have not disappeared". When I say tribals, let me make one thing clear; the word 'Scheduled Tribe' came after the Constitution was adopted. I know for a fact that there are tribals who are not 'scheduled'. But they live in the forests. I know for a fact that there are Scheduled Castes, there are Backward Classes. There are other communities who have imbided the culture of forests. You will be surprised to know, when I say, that the tribals and the forest dwellers are the most effective conservationists. They live in forests, they live by forests and they live for forests. This is my belief. I say this on record. I will quote this Forest Report which was prepared before 2003. Sixty per cent or 60.04 per cent of the forest cover of the country, and 63 per cent of the dense forests, lie in 187 tribal districts. I will explain what a tribal district is. A tribal district is predominantly inhabited by tribals, about 70 per cent of them. And 187 districts out of 593 districts in the country! Just imagine! The geographical area of these districts is just 33.6 per cent. But we have 16 per cent of the forest cover. Out of 58 districts which have more than 66 per cent of the area under forest cover, 51 happen to be tribal districts. So what we have to do today is to recognise that tribals and forests are integral to each other. There is some kind of a symbiotic relationship which cannot be cut off. This is a something that we have to know. That is why I am reading this Report. Otherwise, it has been laid.

Now, one of the things I need to tell you is that, in these areas, you have no fair-price shops, no healthcare, and no local forest administration.

And they are not the owners of the minor forest produce although the law is there. There is always a fear; they live in constant fear because they do not know when they will be thrown out. They live in a very precarious situation of alienation, both physically and psychologically. So, this is the point. Today, the most important thing is to remove fear from their hearts and give them hope.

And we give them hope. We give them something to think about. It is very important . Now today, what we are trying to do is, ...*(Interruptions)*... they are saying, 'we are today here to break the ice'. But, I think, we are here today to demolish the giant iceberg of cruel poverty. We are trying to break that and bring hope, and that too through a legislation. This is what the people want.

Now, I would like to say something about some of the points that have been raised. I think, some points have been raised about jhum and shifting cultivation. I come from the North-east, I know about it. This is why one of the key objects of this Bill is, it will recognise this culture of the tribal people. This is part of their culture. We are not going to interfere; not at all. I know, in Mizoram, when I was the Governor there, the people sing songs in the glory of jhum cultivation. So, it is part of culture. So, we are not going to interfere in that, apart from whatever we think about it.

Then, some mention has been made about something very important, about the fear in respect of those who are already settled through Government. I want to make a clear and crystal clear statement here that those who are already settled through Government, they should not be disturbed . Some mention was made about, -- it is an important point -- I may not be able to do everything for those living in close proximity of the forests; about those people. We say that if they have land inside the forests, which they cultivate, they will be given the right. If anybody lives outside the forest area --I think, I am replying to some of the points raised by some hon. Members.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Please repeat that, Sir. If they have land...

SHRI P.R. KYNDIAH: Yes, if they have land inside the forest, but live outside, they can come and claim it. ...*(Interruptions)*... But, if there is anything more to be done, I can tell you, I have an open mind, and we will

come back to the House. Then, next, I come to small things, small for us, but big for them. Like the words, 'fuel, fuel wood strewn around'. Well, it can be done in the rules. It will be included in the rules. I think, that point has been raised by two-three speakers. But, more important, then, may I go to the basic quesiton of the thinking of the Government about what is a generation. According to us, it is 25 years, and some others did claim for 30 years, 32 years. Some say, 18 years and some say, 21 years. Now, on this matter, if need be, I will come back to the House. If need be, will come back to the House.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, there was a clear assurance given by the GOM. When we had discussions with them, a clear-cut assurance was given that 25 years will not stand, it will be changed because nobody wanted it. How can you go back to pre-independence period of 1930? There was a clear assurance. ...*(Interruptions)*... Sir, you yourself had assured. Now, why are you using the words, 'if need be'? You give a categorical assuracne.

SHRI P.R. KYNDIAH: No, no; I said, 'I will come back to the House'.

SHRIMATI BRINDA KARAT: No, Sir. You said, 'if need be'. Please understand. On this, I am with you. I am saying, Sir, that you had agreed. Please don't add the words, 'if need be'. You give a categorical assurance here, Sir, on this what was decided with the GOM, you will bring to the House.

SHRI P.R. KYNDIAH: Was it decided in the GOM? Yes, whatever is decided, why not?

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, when we had a meeting, it was categorically said that 25 years will not be kept.

SHRI P.R. KYNDIAH: With all the respect, we cannot do it now. I have to come back to the House.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Okay, Sir, but then do not say 'if need be'.

SHRI P.R. KYNDIAH: Okay, I apologise. The only thing is, do not you think I am very open?

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, we cannot take it. Because it is the question of lives of millions of the people. Sir, this is going against whatever you have told me. I am sorry to say this.

SHRI P.R. KYNDIAH: But, how do we go about it?

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, you just give an assurance in the House that you will come back on the issue of 'generation'. I am saying you used the word 'if need be'.

SHRI P.R. KYNDIAH: I am saying that we will come back to the House on this issue. What more do you want? This is exactly what you want. I will come back to this House on this issue. What more do you want?

SHRIMATI BRINDA KARAT: Okay, Sir. Do you come back in the next Session of Parliament?

SHRI P.R. KYNDIAH: Yes, naturally. I do not have the time. Tomorrow is the last day of this Session.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Nextly, some mention has been made about carrying bicycles and handcarts. This will be included in the rules because this is important. I know that handcarts and bicycles are the lifeline.

Then, on the schedule of beneficiaries by the Panchayats, it will be done. Another thing which appears to be very sensitive is the composition of the Panchayat Committee. We have already taken a view that the Committee should be balanced. There will be six members. Three are to be nominated by the Panchayat, of which two must be from Scheduled Tribes, and one women; and of the other three representatives, there will be one each from the Revenue, from the Tribal Affairs and from the Forest. Is it all right? I am clear about this. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, the JPC had given a suggestion about the evidence—oral evidence, etc.

SHRI P.R. KYNDIAH: Since we are coming back to the House we will take them up. So many things are said today from that side and this side. I cannot reply to each and every issue. But let me tell you that we are sensitive towards whatever is said over here. And we will come back to the House on the issues which are impediments to the effective implementation of Act. What more do you want? On anything that will impede the effective implementation of the Act, we will come before the House. What more do you want? I am giving you a blank cheque. Is it all right? ...*(Interruptions)*... I thank you, Sir. I will not be able to reply to everything. I request you to please take note of this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is all right. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: India is a signatory to the Indigenous and Tribal Population Convention, 1957, in ILO 107 Convention. We have ratified it in 2003 and in this JPC report also they have given a unanimous decision in 62.5: "All forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers must be rehabilitated strictly in compliance with ILO 107 Convention and in strict compliance with the policy of prior informed concept." Whether we are doing that or not? Sir, can you just inform the House?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Any other clarification ...*(Interruptions)*... Mr. Minister, would you like to react to it?

AN HON. MEMBER: He has already said that he would be coming back to the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI P.R. KYNDIAH: I will come back to the House....*(Interruptions)*...

I have given a very blanket assurance that on any matter which is sensitive or anything, which is impeding the effective implementation of this Act, I will come back to the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now the question is:

That the Bill to recognise and vest the forest rights and occupation in forest land in forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for generations but whose rights could not be recorded; to provide for a framework for recording the forest rights to vested and the nature of evidence required for such recognition and vesting in respect of forest land, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The Motion was adopted.

Clause - 2-- Definitions

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill. First, clause 2. There are four amendments, Nos. 1 and 2 by Shri Kanjibhai Patel and Nos. 3 and 4 by Shrimati Brinda Karat. ...*(Interrutpions)*...

He said he would come back to the House. ...*(Interruptions)*... Are you pressing your amendments?

**श्री कांजीभाई पटेल:** सर, जो प्रोक्सिमिटी पर रहते हैं, मैंने जो अमेंडमेंट दिया था और मंत्री जी ने वैसे कहा भी है, लेकिन इसके बारे में माननीय मंत्री जी का यहां हाउस के सामने कमिटमेंट हो, यह मैं चाहता हूं। दूसरा जो फ्यूल वुड का है, उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, you are not pressing for your amendments. Now, Brindaji.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I just want to read my amendment. Do not get irritated by this. This is going to affect the lives of so many people. "Fuel wood, stones and products from water bodies, including fish and weed", this is my amendment, Sir. What I understand from what he has clearly said is that he is going to include this in the rules. Therefore, I do not press my amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments not pressed. I shall now put clause 2 to vote.

*Clause 2 was added to the Bill.*

Clause 3

**Forest rights of Forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dweller.**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, clause 3, there is amendment No. 5 by Shri Kanjibhai Patel.

**श्री कांजीभाई पटेल:** सर, साइकिल या हैंड कार से जंगल में से कुछ चीजें बाहर निकालने के लिए इन्होंने अपनी स्पीच में कुछ कहा है। ...(व्यवधान)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: You have not taken up my amendment regarding this generation thing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You did not press.

SHRIMATI BRINDA KARAT: This is the most important amendment. ...*(Interrutpions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I said Amendment Nos. 3 and 4. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, let me get this ...*(Interrutpions)*... sir, this generation thing is very important. This is the main thing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have put both the amendments to vote.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Okay, Sir. To carry bicycle and handcart.

श्री उपसभापति: उसे रूल्स में ला रहे हैं। Not pressed. Brindaji, amendment No. 6.

SHRIMATI BRINDA KARAT: About others who have settled in forest areas by Government policy, what is the reply of the Minister on that? ...*(Interruptions)*... He has not said ....*(Interruptions)*... He has given a categorical assurance. ...*(Interruptions)*... It is already over.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put clause 3 to vote.

*Clause 3 was added to the Bill.*

**Clause 4: Recognition of and vesting of forest rights in forest dwelling Scheduled Tribes**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments Nos. 7 and 8 by Shrimati Brinda Karat. Are you withdrawing?

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, on this, my understanding is that the Minister would kindly confirm that he has made a categorical statement that all those who have been settled in forest areas by Government will not be disturbed. Sir, I withdraw that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, you are not pressing. I shall now put Clause 4 to vote.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, amendment No. 8 is there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I was putting both to vote and you said both.

श्रीमती वृंदा कारत: सर, इस तरह मैं कैसे कर सकती हूं? करोड़ों आदिवासियों का सवाल है।

श्री उपसभापति: सबको मालमू है, करोड़ों आदिवासियों का सवाल है। आप बोलिए।

श्री वी॰ हनुमंत राव (आन्ध्र प्रदेश): इतना अच्छा मंत्री कहीं नहीं मिलता है।

श्रीमती वृंदा कारत: हमें तो मिलता है।

श्री उपसभापति: वृंदा जी, मैंने कहा-सात और आठ, You have to explain both amendment Nos. 7 and 8.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Okay, I am sorry, Sir, it is entirely my fault, Sir, "in consultation with independent ecological and social scientists familiar with the area" You have accepted it.

SHRI P.R. KYNDIAH: Yes.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Okay.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, मंत्री जी कुछ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कम से कम खड़े होकर तो बोलें। He is addressing the nation through this House and he is addressing the Chair. When he is making any assurance in the House, he should stand up and speak. By sitting and speaking...(*Interruptions*)... हम क्या मज़ाक कर रहे हैं?...(व्यवधान)... Is it a private affair of two persons? It is not.

श्री उपसभापति: उन्होंने कहा, मैं पहले ही एक्सेप्ट कर चुका हूं।...(व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात): मत बोलिए, आपको मंत्री नहीं बनाएंगे।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put clause 4 to vote.

*Clause 4 was added to the Bill.*

*Clause 5 was added to the Bill.*

**Clause 6: Authorities to vest forest rights in forest dwelling Scheduled Tribes and the procedure thereof.**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments Nos. 9 and 10 by Shrimati Brinda Karat.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, No. 9, "schedule of beneficiaries" is to be added in that.

SHRI P.R. KYNDIAH: I have agreed.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Have you accepted?

MR DEPUTY CHAIRMAN: He is saying that he has already agreed.

SHRIMATI BRINDA KARAT: I Hope the record says that he agrees. (*Interruptions*) He has agreed to all these!

SHRI P. R. KYNDIAH: In fact, when I replied I had explained that this would be included in the rules.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Thank you, Sir, That is all I want it formally.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, both 9 and 10?

SHRI P. R. KYNDIAH: Yes, both.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So you don't press it. I shall now put clause 6 to vote.

*Clause 6 was added to the Bill.*

*Clauses 7 to 13 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment No. 11 for insertion of a new clause 13 A by Shri Kanjibhai Patel.

श्री कांजीभाई पटेल: सर, यह जो ओवर राइडिंग इफेक्ट वाली बात है, वह इतनी महत्व की है कि अगर इसको नहीं रखा जाता है तो कोई यूज़ नहीं रहेगा और दूसरे जो रूल्स हैं, Wild Life Act और Forest Conservation Act, इसके ऊपर प्रिवेल कर जाएंगे, इसलिए इसको इनक्लूड करना चाहिए।

SHRI P.R. KYNDIAH: I have given an assurance that we will take up all these sensitive issues. I will come back to the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, he is not pressing.

*Clause 14 was added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.*

SHRI P.R. KYNDIAH: Sir, I move:

*That the Bill, as amended, be passed.*

*The question was put and the motion was adopted.*

## MESSAGES FROM LOK SABHA

### The Administrative Tribunals (Amendment) Bill, 2006

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 18th December, 2006, agreed without any amendment to the Administrative Tribunals (Amendment) Bill, 2006, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 14th December, 2006."